सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 137, नई दिल्ली, शनिवार 26 जुलाई 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो।

03 लालबाग की झुग्गियों को 31 जुलाई तक खाली करने के निर्देश

06 भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौताः एक क्रांतिकारी कदम

08 गिरती छतें, गिरती ज़मीरः झालावाड़ हादसा और हमारी व्यवस्था की नींव में छुपी मौत

तालाब की भूमि पर बस टर्मिनल के निर्माण को डीटीसी ने बताया बेबुनियाद

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने जल निकाय की भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों को खारिज किया है। एनजीटी में दाखिल हलफनामे में डीटीसी ने कहा कि नजफगढ़ बस टर्मिनल किसी अधिसूचित जल निकाय पर नहीं है बल्कि एमसीडी के स्वामित्व वाली भूमि पर है। डीडीए ने भी पुष्टि की है कि जल निकाय की जिम्मेदारी एमसीडी की है।

संजय बाटला

नई दिल्ली। जल निकाय की 30.5 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर बस टर्मिनल का निर्माण करने के आरोपों को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने बेबुनियाद बताया है। एक आवेदन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में हलफनामा दाखिल कर डीटीसी ने कहा कि संबंधित जल निकाय या तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) या फिर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के स्वामित्व में है। हालांकि, नजफगढ़ बस टर्मिनल किसी भी अधिसूचित जल निकाय पर नहीं है।

हलफनामा में कहा गया कि नजफगढ़ बस टर्मिनल के सबसे नजदीकी जल निकाय टर्मिनल के पीछे है और एमसीडी के स्वामित्व में है। यह भी कहा कि इसकी पुष्टि डीडीए द्वारा दायर हलफनामे से भी होती है। जिसमें डीडीए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डीटीसी टर्मिनल के पास जल निकाय डीडीए द्वारा 2016 में एमसीडी को सौंप दिया गया है और इसके रखरखाव, देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी एमसीडी की है। ऐसे में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि डीटीसी/एमसीडी द्वारा किसी भी जल निकाय पर अतिक्रमण नहीं किया गया है।

अतिक्रमण कर बस टर्मिनल बनाने की पुष्टि की थी

हालांकि, पूर्व मे दाखिल हलफनामे में उत्तर-पश्चिम जिलाधिकारी ने स्वयं डीटीसी द्वारा जल निकाय की भूमि पर अतिक्रमण कर बस टर्मिनल बनाने की पुष्टि की थी। उन्होंने एनजीटी के समक्ष दाखिल हलफनामा में कहा था कि नजफगढ़ गांव में तलाब के रूप में दर्ज 30.5 बिस्वा जमीन पर डीटीसी ने एक बस टर्मिनल व बहुमंजिला व्यवसायिक इमारत का निर्माण कर लिया।

पिछली सुनवाई पर एनजीटी ने डीटीसी को मामले पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। एनजीटी आवेदनकर्ता करतार सिंह सहित अन्य की तरफ से दायर आवेदन पर विचार कर रहा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि तलाब की भूमि पर अतिक्रमण कर सरकारी एजेंसी ने बस टर्मिनल और बहुमंजिला व्यवसायिक इमारत का निर्माण किया है।

सरिता विहार फ्लाईओवर का एक हिस्सा 8 अगस्त तक रहेगा 'बंद', फरीदाबाद से आश्रम जाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी

मरम्मत कार्य के चलते सरिता विहार फ्लाईओवर का बदरपुर से आश्रम की ओर जाने वाला मार्ग 25 जुलाई से 8 अगस्त तक आंशिक रूप से बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। फरीदाबाद से आश्रम जाने वाले वाहन चालक एमबी रोड या ओखला एस्टेट मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।

दिल्ली। मरम्मत कार्य के चलते सरिता विहार फ्लाईओवर का बदरपुर से आश्रम की ओर जाने वाला मार्ग 25 जुलाई से आठ अगस्त तक आंशिक रूप से बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने फरीदाबाद से आश्रम की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की है। तय समयावधि में काम पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग रात दिन काम करेगा।

वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील

सरिता विहार फ्लाइओवर दक्षिणी दिल्ली के व्यस्ततम फ्लाइओवर में से एक है। मरम्मत कार्य के दौरान लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर फरीदाबाद से आश्रम की ओर जाने वाले वाहनों को सरिता विहार फ्लाइओवर की बजाय वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

एडवाइजरी के अनुसार इस दौरान भारी वाहनों की आवाजाही फ्लाइओवर पर पूरी तरह से बंद रहेगी। आपातकालीन वाहनों को अनुमति दी जाएगी, । हालांकि पुलिस ने उन्हें भी बहुत अधिक जरूरत न हो तो वैकल्पिक मार्गों का ही इस्तेमाल करने की बात कही है।

जाम से बचने को इन रास्तों का करें इस्तेमाल

ट्रैफिक पुलिस की ओर से जान एडवाइजरी के अनुसार फरीदाबाद से आश्रम की ओर जाने वाले वाहन चालक एमबी रोड से पुल प्रह्लादपुर और लाल कुआं होते हुए दाएं मुड़कर वाहन चालक मां आनंदमयी मार्ग की ओर चलें। यहां से वाहन चालक क्राउन प्लाजा और गोविंदपुरी से मोदी मिल होते हुए आश्रम की ओर जा सकते हैं। वहीं दूसरे वैकल्पिक मार्ग के रूप में वाहन चालक सरिता विहार फ्लाईओवर के साथ स्लिप रोड का प्रयोग कर ओखला एस्टेट मार्ग से क्राउन प्लाजा, मां आनंदमयी मार्ग, गोविंदपुरी मार्ग से मोदी मिल होते हुए आश्रम की ओर जा सकते हैं।

क्या है दिल्ली मेट्रो का एंटी ड्रैग सिस्टम? अब दरवाजों में नहीं फंसेंगे आपके कपड़े और सामान

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एंटी ड्रैग सिस्टम लगाने की पहल की है। रेड लाइन की एक ट्रेन में यह सिस्टम लगाया गया है और ट्रायल चल रहा है। इस सिस्टम से दरवाजे में कपड़े या सामान फंसने की घटनाएं रुकेंगी जिससे मेट्रो में सफर और भी सुरक्षित हो जाएगा। पुराने कॉरिडोर की सभी ट्रेनों में यह सिस्टम लगाया जाएगा।

नई दिल्ली। मेट्रो में चढ़ने या उतरने की जल्दबाजी में ट्रेन के दरवाजे में कपड़े या कोई सामान फंसने के कारण होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल निगम) ने एंटी ड्रैग सिस्टम लगाने की पहल की है। इसी क्रम में डीएमआरसी ने रेड लाइन की एक मेट्रो ट्रेन के दरवाजों में एंटी ट्रैग सिस्टम लगाने का काम पूरा कर लिया है।

इसका अभी ट्रायल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेड व ब्लू लाइन की चार अन्य ट्रेनों में भी इसे लगाने का काम जल्द पूरा हो जाएगा। इसका ट्रायल सफल होने के बाद पुराने कारिडोर की सभी मेट्रो ट्रेनों के दरवाजों में यह सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे मेट्रो ट्रेन के दरवाजों में साड़ी, दुपट्टे, रूमाल, बैग का फीता इत्यादि फंसने की घटनाएं नहीं होगी और मेट्रो में सफर ज्यादा सुरक्षित होगी।

मौजूदा समय में मेट्रो के दरवाजे में सेंसर लगे होते हैं

मौजूदा समय में मेट्रो के दरवाजे में सेंसर लगे होते हैं। इससे 15 मिलीमीटर तक की मोटाई की कोई भी चीज सामने आने पर दरवाजे बंद नहीं होते। लेकिन इससे पतली चीजें मेट्रो के दरवाजों में फंसने की आंशका रहती है। 14 दिसंबर 2023 को रेड लाइन (रिठाला-शहीद स्थल न्यू बस अड्डा गाजियाबाद) के इंद्रलोक स्टेशन पर मेट्रो के दरवाजे में एक महिला की साड़ी फंस गई थी। इस वजह से महिला मेट्रो के साथ प्लेटफार्म पर घसीटती चली गई। बाद में प्लेटफार्म के अंतिम छोर पर लगे ग्रिल से टकराकर वह प्लेटफार्म से नीचे मेट्रो ट्रैक पर गिरी। इस घटना में गंभीर चोट लगने के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान उस महिला यात्री की मौत हो गई थी। इस घटना से मेट्रो में सुरक्षित सफर पर गंभीर सवाल उठे थे।

ट्रेनों में एंटी ड्रैग सिस्टम लगाने की सिफारिश की गई

मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) ने जांच में मेट्रो ट्रेनों में एंटी ड्रैग सिस्टम लगाने की सिफारिश की गई थी। बाद में केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देश पर पिछले वर्ष जून में डीएमआरसी ने तीन करोड़ की लागत से रेड व ब्लू लाइन की पांच ट्रेनों के 40 कोच में एंटी ड्रैग सिस्टम लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी।

सभी आठ कोच के दरवाजों में एंटी ड्रैग सिस्टम लग गया

डीएमआरसी का कहना है कि एक ट्रेन के सभी आठ कोच के दरवाजों में एंटी ड्रैग सिस्टम लग गया है। चार अन्य ट्रेनों में भी इसे लगाने का काम चल रहा है। स्टेशन से मेट्रो ट्रेनों के खुलने पर दरवाजों के बीच में 0.8 मिलीमीटर तक की पतली चीजें भी फंसने पर यह एंटी ड्रैग सिस्टम सक्रिय हो जाएगा और इमरजेंसी ब्रेक लगने से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी।

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और फेज तीन में बनी पिंक व मजेंट लाइन के स्टेशनों पर प्लेटफार्म स्क्रीन डोर लगाए गए हैं। फेज चार के कारिडोर के स्टेशनों पर भी स्क्रीन डोर लगाए जाएंगे। इसलिए इन कॉरिडोर की मेट्रो में एंटी ड्रैग सिस्टम की खास जरूरत नहीं है लेकिन रेड, ब्लू, यलो, वायलेट व ग्रीन लाइन की सभी मेट्रो ट्रेनों में इसे लगाने की जरूरत है।

प्लेटफार्म पर तैनात किए गए हैं सुरक्षा गार्ड

इंद्रलोक स्टेशन की घटना के बाद कई मेट्रो स्टेशनों के प्लेटफार्म पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। स्टेशन पर ट्रेनों में सभी यात्रियों के सवार होने और सुरक्षा गार्ड द्वारा इशारा करने के बाद ट्रेनें स्टेशन से रवाना होती हैं।

श्रीकृष्ण अपने पैर का अंगूठा क्यों पीते थे ?

श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा हैं। यह सारा संसार उन्हीं की आनन्दमयी लीलाओं का विलास है । श्रीकृष्ण की लीलाओं में हमें उनके ऐश्वर्य के साथ-साथ माधुर्य के भी दर्शन होते हैं। ब्रज की लीलाओं में तो श्रीकृष्ण संसार के साथ बिलकुल बँधे-बँधे से दिखायी पड़ते हैं । उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है बालकृष्ण द्वारा अपने पैर का अंगूठे पीने की लीला ।

श्रीकृष्णावतार की यह बाललीला देखने, सुनने अथवा पढ़ने में तो छोटी-सी तथा सामान्य लगती है किन्तु इसे कोई हृदयंगम कर ले और कृष्ण के रूप में मन लग जाय तो उसका तो बेड़ा पार होकर ही रहेगा क्योंकि 'नन्हे श्याम की नन्ही लीला, भाव बड़ा गम्भीर रसीला ।'

श्रीकृष्ण की पैर का अंगूठा पीने की लीला का भाव

भगवान श्रीकृष्ण के प्रत्येक कार्य को संतों ने लीला माना है जो उन्होंने किसी उद्देश्य से किया । जानते हैं संतों की दृष्टि में क्या है श्रीकृष्ण के पैर का अंगूठा पीने की लीला का भाव ?

संतों का मानना है कि बालकृष्ण अपने पैर के अंगूठे को पीने के पहले यह सोचते हैं कि क्यों ब्रह्मा, शिव, देव, ऋषि, मुनि आदि इन चरणों की वंदना करते रहते हैं और इन चरणों का ध्यान करने मात्र से

उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ? कैसे इन चरण-कमलों के स्पर्श मात्र से गौतमऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की शिला से सुन्दर स्त्री बन गई ?

कैसे इन चरण-कमलों से निकली गंगा का जल (गंगाजी विष्णुजी के पैर के अँगूठे से निकली हैं अतः उन्हें विष्णुपदी भी कहते हैं) दिन-रात लोगों के पापों को धोता रहता है ? क्यों ये चरण-कमल सदैव प्रेम-रस में डूबी गोपांगनाओं के वक्षःस्थल में बसे रहते हैं ? क्यों ये चरण-कमल शिवजी के धन हैं । मेरे ये चरण-कमल भूदेवी और श्रीदेवी के हृदय-मंदिर में हमेशा क्यों विराजित हैं ।

जे पद-पदुम सदा शिव के धन, सिंधु-सुता उर ते नहिं टारे।

जे पद-पदुम परसि जलपावन, सुरसरि-दरस कटत अघ भारे।।

जे पद-पदुम परसि रिषि-पत्नी, बलि-मृग-ब्याध पतित बहु तारे।

जे पद-पदुम तात-रिस-आछत, मन-बच-क्रम प्रहलाद सँभारि।।

भक्तगण मुझसे कहते हैं कि—

हे कृष्ण ! तुम्हारे चरणारविन्द प्रणतजनों की कामना पूरी करने वाले हैं, लक्ष्मीजी के द्वारा सदा सेवित हैं, पृथ्वी के आभूषण हैं, विपत्तिकाल में ध्यान करने से कल्याण करने वाले हैं ।

भक्तों और संतों के हृदय में बसकर मेरे चरण-कमल सदैव उनको सुख प्रदान क्यों करते हैं ? बड़े-बड़े ऋषि मुनि अमृतरस को छोड़कर मेरे चरणकमलों के रस का ही पान क्यों करते हैं । क्या यह अमृतरस से भी ज्22यादा स्वादिष्ट है ?

विहाय पीयूषरसं मुनीश्वरा,
ममांघ्रिराजीवरसं पिबन्ति किम्।
इति स्वपादाम्बुजपानकौतुकी,
स गोपबालः श्रियमातनोतु वः।।

अपने चरणों की इसी बात की परीक्षा करने के लिये बालकृष्ण अपने पैर के अंगूठे को पीने की लीला किया करते थे

बतौर साधक यह जिम्मेदारी हमारी स्वयं/खुद की है हम खुद समझ लें क्योंकि दूसरों के परायेपन/ईर्ष्या/द्वेष/घृणा के चलते, उन्हें समझाना संभव नहीं होता। हम सक्षम हो जायें तो जरूर यह बड़े भरोसे की चीज है। हम पहले प्रेम के उपयोग/जानकारी /किताबों के बारे में सोचना बंद करके, गहराई में स्वयं से जुड़ें और स्वस्थ हों तो प्रेम जीवन में छा ही जायेगा। ध्यान रहे कि जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं उतने ही विशाल रुप में, वह सबको छाया, फल और शीतलता का सुख देने में समर्थ होता है।

रतन थियम को श्रद्धांजलि: विश्व पटल पर भारतीय रंगमंच को स्थापित कर गये रतन

ओंकारेश्वर पांडेय

रतन थियम चले गए। दादा २३ जुलाई, २०२५ को गए। मणिपुर रो रहा है। शांति की बात उन्होंने की। उनका रंगमंच चमका। वे कहते थे - "रंगमंच हमारी आत्मा है।" रचनात्मकता के रथियारों से युद्ध के खिलाफ युद्ध लड़ने वाला योद्धा नहीं रहा। अशांत मणिपुर को शांति का संदेश देते देते खामोश हो गये रतन थियम। रतन थियम भारतीय रंगमंच के एक विशाल पर्वत थे।उन्होंने मणिपुरी परंपराओं को विश्व के साथ जोड़ा। उनकी रचनाएँ—महाभारत त्रयी(उरुभंगम, चक्रव्यूह, कर्णभरम)और तैरेंबीगी ईशेई—युद्ध, पहचान और शांति पर गहरी सोच रखती थीं। मणिपुर के मैतेई-कुकी झगड़े से वे दुखी थे और शांति की आवाज़ बने। रतन एक रंगकर्मी या निर्देशक भर नहीं, वह रंग वैज्ञानिक थे जिसने मणिपुर की आत्मा को वैश्विक कैनवास पर उकेरा। उनकी कला आज भी एकता की मिसाल है। उनका जाना भारत और दुनिया को झकझोर रहा है।

२३ जुलाई, २०२५ को रंगमंच की दुनिया एक अनमोल सितारे के बुझने से शोकाकुल हो उठी। रतन थियाम, वह दूरदर्शी नाटककार, निर्देशक और सांस्कृतिक दीपक जिन्होंने 77 वर्ष की आयु में इम्फाल के रिम्स अस्पताल में अंतिम प्रणाम लिया। उनका निधन केवल भारतीय रंगमंच के लिए ही नहीं, अपितु वैश्विक मंच के लिए भी एक युग का अंत है, जहां उनके कार्य ने सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों को लाँघकर मानव आत्मा की सार्वभौमिक पुकार को स्वर दिया। उन्हें केवल रंग कलाकार या निर्देशक कहना उनके अपार प्रतिभा को कमतर आंकना होगा; मैं कहूंगा कि वे एक रंग वैज्ञानिक थे—एक ऐसे महान रसायनज्ञ, जिन्होंने प्राचीन और समकालीन, स्थानीय और सार्वभौमिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक तत्वों को सानंदित कर रंगमंच को एक अनुपम प्रयोगशाला बनाया। उनका मंच वह पवित्र स्थल था, जहाँ मणिपुर की परंपराएं, वैश्विक सौंदर्यबोध और मानवीय अनुभवों का कच्चा स्पंदन एक अनुपम सत्य और सौंदर्य के रूप में सानंदित हुआ।

रंगमंच को समर्पित जीवन

२० जनवरी, 1948 को मणिपुर के इम्फाल में जन्मे रतन थियाम एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिनकी रचनात्मक यात्रा चित्रकला और लेखन से प्रारंभ होकर रंगमंच में अपनी पराकाष्ठा तक पहुँची। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) से 1974 में स्नातक होने के पश्चात, उन्होंने 1976 में इम्फाल के निकट कोरस रिपर्टरी थिएटर की स्थापना की, जो मणिपुर की संनादित संस्कृति और विश्व के साथ संवाद का एक पवित्र मंदिर बन गया। उनकी रंगमंचीय प्रस्तुतियाँ केवल नाटक नहीं थीं, अपितु युद्ध, पहचान और मानवता की अनंत खोज पर गहन चिंतन थीं।

रतन थियम की महाभारत त्रयी—उरुभंगम (1981), चक्रव्यूह (1984), और कर्णभरम (1989)—तथा उत्तर प्रियदर्शी और तैरेंबीगी ईशेई जैसे कार्य युद्ध, पहचान और मानवता की अनंत खोज पर गहन चिंतन थे। यह त्रयी, जो भास के संस्कृत क्लासिक्स और थियम के मूल चक्रव्यूह पर आधारित थी, प्रतीकात्मक रूप से एक व्यक्ति के संरचित हिंसा के विरुद्ध संघर्ष और उसकी अनिवार्य पराजय को चित्रित करती थी। उरुभंगम में दुर्योधन का टूटा शरीर और आत्मा, चक्रव्यूह में अभिमन्यु का करुणाजनक फँसना और कर्णभरम में कर्ण का अस्तित्वगत संकट विश्व के युद्धों के बीच उभरकर सामने आया। जैसा कि समीक्षक समिक बंद्योपाध्याय ने, डॉ. पिनाक शंकर भट्टाचार्य, बनेश्वर सरथीबाला महाविद्यालय के अंग्रेजी के सहायक प्रोफेसर, के हवाले से कहा, "1981 में भास के उरुभंगम से शुरुआत कर, 1984 में अपने चक्रव्यूह के साथ और 1989 में भास के कर्णभरम के साथ समापन करते हुए, रतन ने एक महाभारत त्रयी पूर्ण की, जो एक व्यक्ति के हिंसा के विश्वव्यापी प्रवाह के सामने अपनी पहचान पर प्रश्न उठाने की थीम से जुड़ी थी।"

थियम का 2014 का मैकबेथ, जिसे मैतेई संदर्भ में मणिपुरी संगीत और थांग-टा के साथ पुनर्गढ़ित किया गया, ने शेक्सपियर के त्रासदी को एक सार्वभौमिक, और विशिष्ट रूप से स्थानीय महत्वाकांक्षा और विनाश की खोज में बदल दिया।

भारत में, थियम का रंगमंच बेजोड़ था, जो मणिपुर की परंपराओं को आधुनिक संवेदनाओं के साथ इस तरह मिश्रित करता था, जैसा कि बादल सरकार के शहरी यथार्थवाद या हबीब तनवीर के लोक प्रयोगों में भी नहीं दिखता।

थियम का मंच वह स्थान था जहाँ मणिपुर का सौंदर्यशास्त्र विश्व की रंगमंचीय परंपराओं से मिला, जिसने उनकी विरासत को बेजोड़ दूरदर्शी के रूप में स्थापित किया। उनके नाटक मणिपुर के अशांत सामाजिक-राजनैतिक परिदृश्य का दर्पण थे, जो जातीय संघर्षों, विद्रोहों और युद्ध के दागों को प्रतिबिंबित करते थे। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा था, "युद्ध बच्चों को प्रभावित करता है। युद्ध महिलाओं को प्रभावित करता है; यह उन्हें वेश्या बना देता है। यह सब सामान्य नहीं है।" उनका रंगमंच युद्ध के खिलाफ एक युद्ध था, जो कला, सहानुभूति और अथक रचनात्मकता के रथियारों से लड़ा गया।

वैश्विक समानताएँ: सीमाहीन रंगमंच

रतन थियम का कार्य वैश्विक प्रभावों का एक ताना-बाना था, फिर भी यह मणिपुर की मिट्टी में गहरे जड़ा हुआ था। समीक्षकों ने उन्हें ग्रोटोव्स्की के साथ रखा, जिनके न्यूनतम, रस्मी रंगमंच ने आध्यात्मिक उत्कर्ष की खोज की, और ब्रूक के साथ, जिनके अंतरसांस्कृतिक प्रयोगों ने आधुनिक प्रदर्शन को पुनर्परिभाषित किया। ग्रोटोव्स्की की तरह, थियम ने रंगमंच को इसकी भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई तक खंगाला, अनुशासित कोरियोग्राफी और मंत्रमुग्ध करने वाले सामूहिक संगीत का उपयोग कर प्राचीन सत्य को उजागर किया। ब्रूक की तरह, उन्होंने नाट्य शास्त्र, नोह, काबुकी और ग्रीक नाटकों से प्रेरणा लेकर एक ऐसी रंगमंचीय भाषा रची, जो ओस्लो के इब्सन उत्सव से लेकर सियोल के थिएटर ओलंपियाड तक विश्व भर के दर्शकों से संवाद करती थी। उनकी व्लेन वी डेड अवेकन (2010), इब्सन की मणिपुरी व्याख्या, ने अपनी अतियथार्थवादी सौंदर्यता और सामूहिक संगीत की तीव्रता से नॉर्वे के दर्शकों को स्तब्ध कर दिया, यह सिद्ध करते हुए कि थियम की दृष्टि किसी भी सांस्कृतिक संदर्भ में गूंज सकती थी।

थियम की स्थानीय और सार्वभौमिक को मिश्रित करने की क्षमता जापान के तदाशी सुज़ुकी के कार्य के समान थी, जिनके सुज़ुकी मेथड ने शारीरिकता और सांस्कृतिक स्मृति पर जोर दिया, ठीक वैसे ही जैसे थियाम ने थांग-टा और मैतेई रीति-रिवाजों का उपयोग किया। उनकी दृश्यात्मक रूप से भव्य प्रस्तुतियाँ, जिन्हें "काव्यात्मक और अतियथार्थवादी" कहा गया, एरियान म्नुश्किन के थिएट्रे डु सोलेइल की ओपेरा-जैसी भव्यता को प्रतिबिंबित करती थीं, जहाँ मिथक और इतिहास जीवंत दृश्यों में टकराते थे।

फिर भी, थियम अनूठे रहे—मणिपुर के एक सपूत, जिन्होंने इसकी कहानियों, संघर्षों और संनादित सौंदर्य को विश्व मंच तक पहुँचाया। जैसा कि उन्होंने कहा था, "मणिपुर अपनी संनादित संस्कृति के कारण सुंदर है यह दृष्टिकोण हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है और यही वह है जिसने हमारी कलाओं को महान बनाया।"

थियम का प्रभाव न केवल उनकी प्रस्तुतियों में, बल्कि उन लोगों के शब्दों में भी झलकता है जिन्होंने उनकी कला को देखा। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "उनकी कला के प्रति अटूट समर्पण, उनकी दृष्टि और मणिपुरी संस्कृति के प्रति प्रेम ने न केवल रंगमंच की दुनिया को समृद्ध किया, बल्कि हमारी पहचान को भी।" रंगमंच विद्वान और समीक्षक समिक बंद्योपाध्याय ने उन्हें "मंच का कवि" कहा, जो अपने नाटकों में "विविध दृष्टिकोणों का तर्कसंगत और बहुआयामी विश्लेषण" करने की उनकी क्षमता को रेखांकित करता है। अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी, थियम की एनएसडी सहपाठी, ने उन्हें "अध्ययनशील, जिज्ञासु और हमेशा ध्वनियों और गतियों के साथ प्रयोग करने वाला" बताया, जो उनकी अथक नवाचार की गवाही देता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, द ऑक्सफोर्ड कम्पैनियन टू थिएटर एंड परफॉर्मेंस ने उन्हें "भारत के सबसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त निर्देशक" के रूप में सराहा, जो "वैश्विक संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाली दृश्यात्मक रूप से भव्य प्रस्तुतियों" के लिए प्रसिद्ध थे।एक्स पर पोस्ट्स ने इस श्रद्धा को प्रतिबिंबित किया जहाँ उपयोगकर्ताओं ने उन्हें "मणिपुरी रंगमंच का दिग्गज" और "दूरदर्शी प्रतीक" कहा, जिनके कार्य ने "प्रदर्शन में आधुनिकता लाई।" उनका अंतिम नाटक, तैरेंबीगी ईशेई, जो 17 फरवरी, २०२५ को दिल्ली में प्रस्तुत हुआ, पर्यावरणीय सर्वनाश पर एक मार्मिक चिंतन था, जो मानवता के भविष्य के प्रति उनकी आजीवन चिंता का एक उपयुक्त समापन था।

एक देदीप्यमान विरासत

जब थियम जीवित थे और अपनी गर्जना से रंगमंच को जीवंत कर रहे थे, तब मीडिया ने उन्हें एक क्रांतिकारी के रूप में सराहा। द हिंदू (2018) ने उन्हें "प्रख्यात रंगमंच निर्देशक और कवि" के रूप में वर्णित किया, जिनके कार्य ने डिजिटल अलगाव से लेकर वैश्विक हिंसा तक "आधुनिकता के अंधेरे समय" से जूझा। द इंडियन एक्सप्रेस (२०२०) ने रंगमंच की जड़ों के आंदोलन में उनकी भूमिका की प्रशंसा की, यह उल्लेख करते हुए कि उनके नाटकों ने औपनिवेशिक रूढ़ियों को चुनौती दी और मणिपुरी सौंदर्यशास्त्र के माध्यम से भारतीय पहचान को पुनर्जनन दिया। इंडिया टुडे (२०१८) ने थियम के इस विश्वास को उद्धृत किया कि "विविध कला प्रथाएँ हमें मानव होने का तरीका सिखाती हैं और इस ब्रह्मांड में हमारा स्थान दिखाती हैं," एक दर्शन जो 8वें थिएटर ओलंपिक्स में उनकी प्रस्तुतियों में स्पष्ट था।

उनके पुरस्कार—संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1987), पद्म श्री (1989), कालिदास सम्मान (1997), संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप (२०१२), और मणिपुर का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड (२०२५)—उनकी इस विरासत के केवल मामूली पुष्टिकरण थे, जिसे मापना असंभव है।

रंगमंच वैज्ञानिक की विरासत का संरक्षण

रतन थियम का निधन एक शून्य छोड़ गया है, किंतु उनकी विरासत को मलिन नहीं होने देना चाहिए। इम्फाल में उनका कोरस रिपर्टरी थिएटर, एक सांस्कृतिक दीपस्तंभ, को उनके कार्य का जीवंत संग्रहालय बनाकर समर्थन देना चाहिए, जो भविष्य के कलाकारों को उनके अंतर्विषयी दृष्टिकोण में प्रशिक्षित करे। जैसा कि थियम ने जनवरी २०२५ में निंगथम खुमहेई शुमंग लीला उत्सव में वकालत की थी, मणिपुर में एक विश्वस्तरीय सांस्कृतिक परिसर की स्थापना राज्य की कलात्मक विरासत को पोषित करने के लिए आवश्यक है।

उनके स्क्रिप्ट्स, रिकॉर्डिंग्स और प्रस्तुति नोट्स को डिजिटाइज कर विश्व भर के विद्वानों और अभ्यासियों के लिए सुलभ करना चाहिए, ताकि चक्रव्यूह और उत्तर प्रियदर्शी जैसे कार्य प्रेरणा देते रहें। शैक्षिक संस्थानों, विशेष रूप से एनएसडी, जहाँ थियम ने निदेशक (1987–88) और अध्यक्ष (२०१३–17) के रूप में सेवा दी, को उनकी पद्धतियों को पाठ्यक्रम में समाहित करना चाहिए, जो पारंपरिक और समकालीन रूपों के संनादन पर बल देता हो। भारत रंग महोत्सव जैसे उत्सवों, जहाँ थियम के नाटकों को सराहा गया, को उनके कार्यों के लिए रेट्रोस्पेक्टिव समर्पित करने चाहिए, जो स्थानीय और वैश्विक दर्शकों से संवाद करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करें। इसके अतिरिक्त, उनकी एकता की पुकार—"विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में एकता का सार ही एकता ला सकता है"—को मणिपुर के जातीय विभाजनों को कला के माध्यम से जोड़ने के प्रयासों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

अंत में

रतन थियम केवल रंगमंच निर्माता नहीं थे; वे एक दार्शनिक, विद्रोही, स्वप्नदृष्टा थे, जिन्होंने रंगमंच को सामाजिक परिवर्तन और आध्यात्मिक जागरण का माध्यम माना। उनका मंच एक पवित्र स्थान था, जहाँ मणिपुर की कहानियाँ—उसका दर्द, उसका सौंदर्य, उसका संनादन—एक ऐसी आवाज बनकर उभरी, जो महाद्वीपों को पार कर गूँजी। जैसा कि उन्होंने एक बार विलाप किया था, "डिजिटल युग ने सुनिश्चित किया है कि अतीत मायने नहीं रखता," फिर भी उनका कार्य सांस्कृतिक स्मृति की स्थायी शक्ति का एक विद्रोही प्रमाण है।

थियम को खोना एक मार्गदर्शक तारे को खोने जैसा है, किंतु उनकी रोशनी हर उस कलाकार में चमकती रहेगी जिसे उन्होंने प्रेरित किया, हर उस दर्शक में जिसे उन्होंने प्रभावित किया, और हर उस मंच पर जो उनके जितना साहसपूर्वक स्वप्न देखने का साहस करेगा। श्रद्धांजलि ओजा पद्म श्रीरतन थियम। आपकी आत्मा शांति में विश्राम करे। आपका रंगमंच एक क्रांति था, आपका विज्ञान एक रहस्योद्घाटन, और आपकी विरासत एक शाश्वत ज्योति। जैसा कि एक एक्स उपयोगकर्ता ने मार्मिक रूप से लिखा, "नायक याद किए जाते हैं, किंतु किंवदंतियाँ कभी मरती नहीं। वे हमारे हृदय में सदा रहेंगे।" (इम्फाल में ब्राउन नोंगमैथम के सहयोग से)

ओंकारेश्वर पांडे

ओंकारेश्वर पांडे दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व रंगमंच कलाकार हैं, जिन्हें प्रदर्शन कला के प्रति गहरा लगाव है। 1990 के दशक में, उन्हें गुवाहाटी उत्सव में रतन थियम की प्रतिष्ठित त्रयी को देखने और उसकी समीक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक अनुभव जिसने भारतीय रंगमंच में थियम के क्रांतिकारी योगदान के प्रति उनकी प्रशंसा को गहराई से आकार दिया।

मोदी की EU के साथ कूटनीति

शिवानन्द मिश्रा।

मोदी की कूटनीति बुरी तरह विफल रही है, इसलिए उनका अंत हो गया है। यूरोपीय संघ ने नयारा तेल रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं, वे मूर्ख हैं। इस बार भारत ने वाकई एक बड़ा दांव खेला है।

ताजा घटनाक्रम है कि तीन दिन पहले, यूरोपीय संघ ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी, नयारा एनर्जी पर रूसी तेल को रिफाइन करने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके बाद, एक अमेरिकी सीनेटर ने रूस के साथ तेल व्यापार जारी रखने पर ₹भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बादद करने की खुली धमकी दी थी।

हालांकि, भारत ने इसका कड़ा जवाब दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत पश्चिमी दबाव के आगे नहीं झुकेगा।

नई दिल्ली ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की नीतियाँ भारत में बनती हैं—वाशिंगटन या ब्रुसेल्स में नहीं।

नयारा एनर्जी ने यूरोपीय संघ के एकतरफ़ा प्रतिबंधों को खारिज कर दिया और अंतरराष्ट्रीय अदालतों में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

अब यूरोपीय संघ गहरे संकट में है, कैसे?

यूरोपीय संघ ने भारत से तेल आयात रोक दिया है लेकिन इससे यूरोप में ईंधन संकट पैदा हो गया है। इस बीच, नायरा भारत में 70,000 करोड़ का निवेश कर रही है और पीछे हटने के बजाय अपने परिचालन का विस्तार कर रही है।

अब एक बड़ा झटका लगा है. भारत ने अपने डीज़ल निर्यात को यूरोप से अफ्रीका और एशिया (बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, आदि) की ओर मोड़ दिया है। अब समझ में आया कि मोदी जी अफ्रीका क्यों गए थे लेकिन, एक हास्य कलाकार से राजनेता बने व्यक्ति मोदी जी का मज़ाक उड़ा रहे थे।

यह बदलाव सिर्फ़ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक है।

यूरोपीय संघ की कार्रवाई ने एक सीधी चेतावनी दी जो तब देखी गई जब एक ब्रिटिश पेट्रोलियम टैंकर ने भारत में लोडिंग रद्द कर जो पश्चिमी देशों के बढ़ते विरोध का संकेत था।

तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट रूप से कहा: भारत रूस, सऊदी अरब या ब्राज़ील से, चाहे वह किसी से भी हो, किफायती, दीर्घकालिक तेल खरीदना जारी रखेगा।

भारत केवल बचाव ही नहीं कर रहा है—वह जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है:

1. कानूनी कार्रवाई: भारत वैश्विक व्यापार कानूनों के उल्लंघन के लिए यूरोपीय संघ को विश्व व्यापार संगठन में ले जाने की योजना बना रहा है।

2. ऊर्जा स्वायत्तता: भारत पश्चिमी तुष्टिकरण के लिए अपने रणनीतिक निर्णयों से समझौता करने से इनकार करता है।

3. विविध आपूर्ति: भारत ने तेल आपूर्ति अप्रभावित रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और अन्य देशों से संपर्क किया।

जहाँ यूरोप ने रूसी कच्चे तेल को परिष्कृत करने के लिए भारत को दंडित करने की कोशिश की, वहीं वह खुद कज़ाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे छद्म मार्गों से रूसी तेल खरीदता है। यह पश्चिम के दोहरे मानदंडों को उजागर करता है।

डरने के बजाय, भारत ने इस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया—शोधन क्षमता को 300 एमएमटी से आगे बढ़ाया और अफ्रीका और आसियान देशों में ईंधन वितरण का विस्तार किया। दक्षिण अफ्रीका, घाना, मोज़ाम्बिक, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों के साथ समझौते हुए हैं।

भारत अब सिर्फ़ ईंधन आपूर्तिकर्ता नहीं रहा—यह एक वैश्विक रिफ़ाइनिंग केंद्र और प्रणाली निर्माता बन रहा है। पश्चिमी देश इस बात से चिंतित हैं कि भारत अब नियम बना रहा है।

जामुन के फायदे

जामुन को कभी भी दूध के साथ न लें, जबकि भोजन के बाद नमक लगा कर लेना अत्यंत गुणकारीहै। रासायनिक गुण- जामुन का फल- शीतल, मधुर, रुचिकारक कसैला, रूक्ष, पौष्टिक कफ पित्त व अफारा नाशक तथा शरीर में रक्त की वृद्धि करता है।गुठली-फल तो फल जामुन की गुठली की गिरी में जम्बोलिन ग्लूकोसाइड पाया जाता है।जिसका प्रमुख लक्षण यह है कि यह तत्व स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित होने से रोकता है।अतः मधुमेह या सुगर के रोगियों के लिए इसकी गुठलियोँ का चूर्ण अच्छा फायदा करता है।इसके अतिरिक्त क्लोरोफिल, एल्ब्यूमिन, गेलिक एसिड, रेजिन व चर्बी आदि अनेक बहुमूल्य पदार्थ पाए जाते हैं।इसमे लोह तत्व भी पर्याप्त मात्रा में पायाजाता है।यह लोह तत्व इतना सोम्य व गुणकारक होता है किइससे किसी प्रकार का नुकसान नही हो सकता अपितु यह लोहशरीर में लोह की कमी को पूरा करने के साथ शरीर यकृत (जिगर) और प्लीहा (तिल्ली) आदि शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर लाभकारी परिणाम डालता है अतः शरीर में रक्त की प्रचुर मात्रा में बृद्धि होती है।बृक्ष की छाल- स्वाद में मधुर, कसैली, पाचक, रुक्ष, शरीर के मलों (दोषों) को उनके निकलने वाले मार्गों से ही निकालने वाली है यह रुचिकर पित्त दाह में तत्काल शान्तिकारक औषध है।सिरका- जामुन का सिरका पेट सम्बंधी रोगों के लिए लाभकारक है।

रोग और जामुन-

1 मधुमेह. (अ)जामुन की गुठली का चूर्ण 5ग्रा.दिन में दो बार शहद से या जल के साथ लेते रहने से मूत्र में शक्कर की मात्रा कम हो जाती है।

(ब)जामुन की गुठली को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर रख लें। नियमित रूप से आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शामपानी के साथ इसका सेवन करें। जामुन की छाल को सुखाकर उसे जलाएं और राख बनाकर छान लें। फिर इसे बोतल में भरकर रख लें। इसके सेवन से सुबह शाम 60-65 मिली ग्रामकी मात्रा में खाली पेट पानी के साथ इसके सेवन करने से डायबिटीज नियंत्रित रहता है।परहेज- चावल आलू शक्कर व मीठे पदार्थों का सेवन बन्द कर दें।जौ चने की रोटी, गाय का फीका दूध, मक्खन फल शाक, फूलशाक आदि का सेवन करें।

2 मोतीझरा. जामुन के कोमल पत्ते, गुलदाउदी के फूल, काली मिर्च समान भाग लेकर जल के साथ पीस लें। मोतीझरा के रोगी को पिलाएं तुरन्त शान्ति मिलेगी। रोग भी दूर होगा।

3 रक्त प्रदर. महिलाओं की व्याधि रक्तप्रदर में जामुन की गिरी का चूर्ण शक्कर में मिलाकर दिन में तीनवार सेवन करने से रक्त प्रदर में लाभ मिलता है।

4 बार बार पेशाव जाना(बहुमूत्र). जामुन की गिरी का बारीक चूर्ण इसी चूर्ण के बराबर कालेतिल साफ करके मिला लें। 10-10 ग्रा.सुबह शाम दूध से लें बहुमूत्र दूर हो जाता है।

5 आवाज बैठना. यदि आपकी आवाज बैठ गई है या मोटी या भारीपन लिए हुए है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैंतो आपको शहर में जामुन की गुठली का पाउडर मिलाकर लेनाचाहिए। इससे आवाज का भारीपन दूर होता है साथ ही आवाज भी साफ हो जाएगी।

6 जामुन और आम की गुठलियों का 2-2 ग्राम पाउडर छाछ केसाथ दिन में तीन बार लेने से पेट दर्द दूर होता है।

7 फोड़े फुंसी. जामुन की गुठली को पानी के साथ घिसकर चेहरे पर लेप करने से मुंहासे और फुंसियां दूर होती हैं और चेहरे का सौंदर्य निखरता है।

8 आग से जले के घाव में. आग से जलने पर घाव बन गया हो तो जामुन की छाल की राख नारियल तेल के साथ मिलाकर घाव लगाने से लाभ होता है।

9 मंजन. जामुन की छाल को छाया में सुखाकर बारीक पीसकर कपडे से छान लें। इसका प्रयोग मंजन के रूप में करें। इससे दांत मजबूत होते हैं,

साथ ही पायरिया और दांत दर्द से भी छुटकारा मिलता है।

10 उल्टियों में. जामुन की छाल को छाया में सुखाकर उसकी भस्म शहद में मिला कर चाटने से उल्टियों में लाभहोता है।

कारगिल विजय दिवस आज

हर साल 26 जुलाई को मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस भारत की तारीख में एक काफी अहम दिन है। यह 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मुल्क के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करता है।

कारगिल विजय दिवस का इतिहास

==========

कारगिल विजय दिवस का इतिहास 1971 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध से जुड़ा है, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान 'बांग्लादेश' नाम से एक अलग देश बना। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच एक-दूसरे के साथ टकराव जारी रहा, जिसमें आसपास के पहाड़ी इलाकों पर सैन्य चौकियां तैनात करके सियाचिन ग्लेशियर पर हावी होने की लड़ाई भी शामिल थी। उन्होंने 1998 में अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण भी किया, जिसके कारण दोनों के बीच लंबे समय से दुश्मनी चलती रही। इसलिए, शांति और स्थिरता बनाए रखने और तनाव को हल करने के लिए, फरवरी 1999 में 'लाहौर डिक्लेरेशन' पर साइन करके कश्मीर मुद्दे के द्विपक्षीय शांतिपूर्ण समाधान की ओर कदम बढ़ाने की कसम खाई गई।

पाकिस्तान ने जब नियंत्रण रेखा पर किया कब्जा

==========

पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने नापाक चाल चलते हुए कश्मीर और लद्दाख के बीच लिंक तोड़ने और अशांति पैदा करने के लिए, उत्तरी कारगिल में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के भारतीय इलाके में घुसपैठ की और ऊंची पहाड़ी के चोटियों पर कब्जा कर लिया। जब भारत को मई 1999 में घुसपैठ का पता चला, तो भारतीय सेना को 'ऑपरेशन विजय' शुरू करना पड़ा और कारगिल युद्ध हुआ। यह संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के कारगिल जिले और एलओसी पर मई से जुलाई 1999 तक चला। करीब दो महीनों तक दुर्गम पहाड़ी इलाके में भीषण युद्ध चला। 'ऑपरेशन विजय' के तहत भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में कामयाब रही और टाइगर हिल और दूसरे रणनीतिक ठिकानों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया।

26 जुलाई, 1999 को तीन महीने के संघर्ष के बाद भारतीय सैनिकों ने ये जीत हासिल की। युद्ध में भारत की जीत, भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है।

कारगिल विजय दिवस का महत्व

==========

कारगिल विजय दिवस का आयोजन राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का भी एक सशक्त प्रतीक है। कारगिल युद्ध ने भारत के सभी कोनों से लोगों को सेना के समर्थन में एकजुट किया।

इसके अलावा, युद्ध की बहादुरी और वीरता की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं, उनमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और समर्पण की भावना पैदा करती हैं। कारगिल विजय दिवस इसलिए भी मनाया जाता है कि शहीदों के बलिदानों को भुलाया न जाए।

श्री राजेश चंद्रा (IRS) आयकर आयुक्त, को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उत्कृष्ट सेवा सम्मान

यह सम्मान आयकर विभाग के उन प्रयासों की सराहना का प्रतीक है, जो देश की राजस्व व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और उत्तरदायी बनाने की दिशा में किए जा रहे हैं।--

नई दिल्ली,संजय साग़र सिंह। भारत सरकार के आयकर विभाग में उल्लेखनीय योगदान के लिए आज एक गरिमामय समारोह में आयकर आयुक्त (नई दिल्ली) श्री राजेश चंद्रा (IRS) को भारत की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें विभाग में उनके उत्कृष्ट कार्य, प्रशासनिक दक्षता और कर सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रदान किया गया।

श्रीमती सीतारमण ने इस अवसर पर कहा कि अधिकारियों की निष्ठा और कार्य के प्रति समर्पण ही आयकर विभाग की साख को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता और पारदर्शी कार्यप्रणाली से करदाताओं के बीच विश्वास में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान आयकर विभाग के उन प्रयासों की सराहना का प्रतीक है, जो देश की राजस्व व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और उत्तरदायी बनाने की दिशा में किए जा रहे हैं।

सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा के इंदिरा कैंप और रोहताश नगर के लालबाग की झुग्गियों को 31 जुलाई तक खाली करने के निर्देश- आतिशी

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। गरीब विरोधी भाजपा सरकार का बुलडोजर अब सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग के इंदिरा कैंप और रोहताश नगर के लालबाग की झुग्गियों पर चलेगा। इन झुग्गियों को खाली करने के लिए नोटिस लगा दी गई है। इसके बाद से यहां रह रहे लोगों में अफरा-तफरी का माहौल है। लोग अपने सिर से छत छीनने के डर से बेहद परेशान हैं। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने शुक्रवार को यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान पीएम मोदी और भाजपा द्वारा 'जहां झुग्गी-वहां मकान' देने की नहीं, बल्कि 'जहां झुग्गी वहां मैदान' बनाने की गारंटी दी गई थी। आम आदमी पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है। हम इन झुग्गियों को बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन लड़ाई लड़ेंगे।

शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने शालीमार बाग से ''आप'' की पूर्व विधायक वंदना कुमारी, शालीमार बाग से पार्षद जलज चौधरी और रोहताश नगर से पार्षद शिवानी पांचाल के साथ पार्टी मुख्यालय पर इस मुद्दे पर संयुक्त प्रेसवार्ता की। आतिशी ने कहा कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार में कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर झुग्गीवाले को मकान मिलेगा। गरीबों को 'जहां झुग्गी, वहां मकान' लिखे कार्ड दिए गए। मोदी ने वादा किया था कि जब तक मकान नहीं मिलता, एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। लेकिन पिछले छह महीनों से, जब से भाजपा की चार इंजन की सरकार बनी, एक-एक कर गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।

आतिशी ने कहा कि इंदिरा कैंप की झुग्गियों में लोग 1990 के दशक से रह रहे हैं। इन लोगों को तत्कालीन दिल्ली प्रशासन ने टोकन और कार्ड दिए थे। यहां लोग 35 साल से भी ज्यादा समय से लोग रह रहे हैं। इसके बाद भी भाजपा की चार इंजन की सरकार इन गरीबों के घरों पर बुल्डोजर चलाने वाली है। इसी तरह, शहादरा की जीटी रोड पर लाल बाग की झुग्गियों में भी 31 जुलाई को बुलडोजर चलाने का नोटिस लगा दिया गया है। लालबाग में भी लोगों के पास दिल्ली प्रशासन द्वारा 1990 में दिए गए अलॉटमेंट कार्ड हैं। 1990 से अब तक किसी सरकार ने इनके घर नहीं तोड़े, लेकिन जैसे ही चार इंजन वाली भाजपा की सरकार आई है, एक के बाद एक गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने की करवाई शुरू की जा रही है।

इस दौरान ''आप'' नेता व शालीमार बाग से पूर्व विधायक वंदना कुमारी ने कहा कि बृहस्पतिवार को शालीमार बाग के इंदिरा कैंप में दोपहर करीब 2 बजे अचानक अफरा-तफरी मच गई। एक नोटिस चिपकाई गई, जिसमें लिखा था कि 15 दिन में मकान खाली कर लें। लोग दहशत में और परेशान थे। समझ नहीं पा रहे थे कि 15 दिन में क्या करें। इसी विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता रहती हैं। रेखा गुप्ता बार-बार कहती हैं कि एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगी, लेकिन उनकी ही विधानसभा में पहले भी झुग्गियों पर बुलडोजर चला और अब इंदिरा कैंप में 15 दिन बाद बुलडोजर चलाने की तैयारी है। लोग डरे हुए हैं कि 15 दिन बाद बुलडोजर आएगा, तो वे कहां जाएंगे।

इस दौरान शालीमार बाग से "आप" पार्षद जलज चौधरी ने कहा कि इंदिरा कैंप मेरे वार्ड 55 में आता है। जब हम नोटिस लगने के बाद वहां पहुंचे, तो लोगों में बहुत मायूसी थी। लोगों ने कहा कि मोदी जी ने वादा किया था कि दिल्ली की एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी और 'जहां झुग्गी, वहां मकान' मिलेगा। लेकिन हर मां, बहन, बुजुर्ग और युवा मायूस थे। किसी के घर में रात को खाना नहीं बना। लोग पूरी रात रोते रहे, परेशान थे और कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था।

रोहतास नगर से "आप" पार्षद शिवानी पांचाल ने कहा कि हमारे वार्ड में बृहस्पतिवार शाम 4 बजे नोटिस लगाया गया कि 31 जुलाई तक झुग्गियां खाली करनी होंगी। लोगों ने मुझसे कॉल कर कहा कि उन्हें धमकाया जा रहा है। पूरी दिल्ली में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और लाल बाग की झुग्गियों को भी बेघर करने की धमकी दी जा रही है। आज सुबह मैं वहां गई, जहां एक छोटी बच्ची ने पूछा कि अगर उनका घर टूट गया, तो वे कौन से स्कूल जाएंगे। हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि वे देश के भविष्य को किस अंधकार में धकेल रहे हैं? लाल बाग की झुग्गियों में भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्रियों ने रात बिताई थी, बच्चों के साथ कैरम खेला था। अब वही लोग इन झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। वे कहां हैं? हम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। भाजपा की तानाशाही के खिलाफ हम हमेशा गरीबों के साथ लड़ेंगे।

बिजली की घंटों कटौती से कानपुर में बिगड़ी मरीजों की हालत : कई बेहोश

सुनील बाजपेई

कानपुर। भीषण गर्मी के पक्ष में घंटों की बिजली कटौती ने यहां कई इलाकों के लाखों लोगों को बेहाल कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा मरीजों की हालत खराब रही। इनमें से कई भीषण गर्मी के फलस्वरुप बेहोश भी हो गए। वहीं केस्को ने बिजली कटौती की वजह कराये जाने वाले कार्य बताए।

केस्को द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के मुताबिक एबी केबल डालने, सर्किट लगाने, 11केवी पैनल जोड़ने आदि कार्यों के कराने के चलते आज शुक्रवार को शहर के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। जिसकी वजह से मोहन गेस्ट हाउस, गौतम विहार, कृष्णा बैंक्वेट, न्यू बारासिरोही रोड और आसपास के क्षेत्र में सुबह साढ़े दस से लेकर शाम चार बजे तक बिजली नहीं रही।

इसीतरह से गुंजन विहार, बंबा रोड क्षेत्र में सुबह नौ बजे से लेकर शाम चार बजे तक, बजारिया चौक, चुन्नीगंज, कर्नलगंज, सीसामऊ, लकड़मंडी में सुबह दस से दोपहर 12 बजे तक, राजेंद्रनगर और अर्रा में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक, ओल्ड गुजैनी-1, कस्टम कॉलोनी, न्यू गुजैनी-1, अशोक कालिया, बर्रा गांव में सुबह साढ़े 10 से लेकर साढ़े 11 बजे तक, रविदासपुरम में सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर डेढ़ बजे तक, गंगागंज में सुबह दस बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बिजली गायब रहने से लोग बहुत बेहाल रहे। जिसमें सबसे ज्यादा खराब हालत बीमार लोगों की रही। इस दौरान बिजली की कटौती ने भीषण गर्मी की वजह से कई लोगों को बेहोश भी कर दिया।

देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों, नागरिक समाज समूहों ने फिलिस्तीनी नरसंहार पर पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। भारत के प्रमुख मुस्लिम निकायों, धार्मिक विद्वानों और नागरिक समाज समूहों ने सामूहिक रूप से फिलिस्तीन संकट पर एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें भारत सरकार और वैश्विक शक्तियों से हस्तक्षेप करने और गाजा में जारी अत्याचारों को रोकने की अपील की गयी है।

फिलिस्तीन पर संयुक्त बयान

हम, भारत के अधोहस्ताक्षरी मुस्लिम संगठनों के रहनुमा, इस्लामी विद्वान और भारत के शांतिप्रिय नागरिक गाजा में हो रहे नरसंहार और मानवीय संकट की कड़ी निंदा करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मूकदर्शक नहीं रह सकता। हम सभी देशों से इज़राइल के साथ सैन्य और आर्थिक संबंध तोड़ने और अवैध कब्जे को समाप्त करने के संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान के समर्थन की अपील करते हैं। हम सभी मुस्लिम बहुल देशों से आग्रह करते हैं कि वे इस तबाही को रोकने के लिए इज़राइल और अमेरिका पर कड़ा दबाव डालें।

भारत ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ितों के साथ खड़ा रहा है; यह उस विरासत को पुनः पुष्ट करने का समय है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह फ़िलिस्तीनी जनता के न्यायोचित संघर्ष में उनके साथ दृढ़ता से खड़े होकर अपनी दीर्घकालिक नैतिक और कूटनीतिक परंपरा का सम्मान करे। भारत को इजरायल की क्रूर कार्रवाइयों की निंदा करनी चाहिए, उसके साथ सभी सैन्य और रणनीतिक सहयोग बंद कर देने चाहिए तथा क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयासों का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए। हम भारत सरकार से मानवीय सहायता को बढ़ावा देने की अपील करते हैं तथा गाजा में घिरे नागरिकों तक आवश्यक आपूर्ति - भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा सहायता - का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए मानवीय गलियारों को तत्काल खोलने की मांग करते हैं। हम व्यक्तियों और संस्थाओं से इस नरसंहार में शामिल इज़राइली उत्पादों और कंपनियों का बहिष्कार करने का आह्वान करते हैं। नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक संगठनों को उत्पीड़ितों की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और फ़िलिस्तीनी संघर्ष के बारे में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं का विरोध करना चाहिए।

हम भारत के लोगों से भी शांतिपूर्ण और वैध प्रतिरोध में भाग लेने की अपील करते हैं। एकजुटता मार्च, जागरूकता अभियान, अकादमिक चर्चाएँ और सर्वधर्म सभाएँ आयोजित की जानी चाहिए ताकि यह दिखाया जा सके कि भारतीय विवेक सोया नहीं है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि फिलिस्तीन के प्रति समर्थन राज्य के उत्पीड़न या दमन का लक्ष्य न बने तथा नागरिक बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से एकजुटता व्यक्त कर सकें।

हमारी आवाज़ में राजनीतिक स्वार्थ नहीं, बल्कि हमारे संविधान और हमारी सभ्यता के नैतिक ताने-बाने में निहित सिद्धांतों की झलक हो। नरसंहार के सामने चुप रहना या तटस्थ रहना कूटनीति नहीं है - यह न्याय को कायम रखने में विफलता है। अब गाजा के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े होने का समय है। आइए हम न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और करुणा की अपनी विरासत से प्रेरित हों। हमें मिलकर इस मानवीय त्रासदी को रोकने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए - इससे पहले कि अपूरणीय क्षति हो जाए।

अधोहस्ताक्षरी: *मौलाना अरशद मदनी- अध्यक्ष, जमीयत उलेमा हिंद, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी अध्यक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी अमीर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, मौलाना अली असगर इमाम महदी अमीर मर्कज़ी जमीयत अहल-ए-हदीस, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, महासचिव जमीयत उलेमा-ए-हिंद, मौ ला ना अहमद वली फैसल रहमानी, अमीर शरियत, अमारत ए शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मुफ़्ती मुकर्रम अहमद, इमाम शाही जामा मस्जिद फ़तेहपुरी, मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी, प्रसिद्ध अहल – ए सुन्नत धर्मोपदेशक पूर्व संसद सदस्य (राज्यसभा), मलिक मोतसिम खान, उपाध्यक्ष जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, डॉ. मुहम्मद मंज़ूर आलम, महासचिव आल इंडिया मिल्ली काउंसिल, डॉ. ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान पूर्व अध्यक्ष,दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग,

अब्दुल हफीज, अध्यक्ष, एसआईओ ऑफ इंडिया

मौलाना मोहसिन तक़वी, प्रसिद्ध शिया धर्मोपदेशक और धार्मिक विद्वान

13. प्रोफेसर अख्तरुल वासे, पूर्व कुलपति

कम्फर्ट से केयर तक: हिमालया बेबीकेयर का भारत में 500 से अधिक ब्रेस्टफीडिंग सेंटर का सफर

मुख्य संवाददाता

भारत। माताओं और बच्चों के लिए स्वस्थ शुरुआत को पोषित करने की अपनी सतत प्रतिबद्धता के तौर पर हिमालया बेबीकेयर ने पूरे भारत में 500 से अधिक ब्रेस्टफीडिंग रूम्स की सफलतापूर्वस्थापना की घोषणा की है, जो माताओं को अपने शिशुओं को गरिमा व सुविधा के साथ दूधपिलाने के लिए स्वच्छ और निजी स्थान प्रदान करते हैं।

यह उपलब्धि मातृ कल्याण के बारे में बढ़ती सार्वजनिक जागरूकता के दौर में ब्रांड के स्वच्छ और विचारशील बुनियादी ढांचे के साथ माताओं को समर्थन देने की की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

ये ब्रेस्टफीडिंग रूम देशभर के 27 हवाई अड्डों में स्थित हैं, जिनमें मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और गोवा जैसे प्रमुख ट्रांजिट हब शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित प्रमुख राज्यों के 33 रेलवे स्टेशनों पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा 141 अस्पतालों और विभिन्न मेट्रो शहरों व क्षेत्रीय केंद्रों में अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों में 268 फीडिंग रूम स्थापित किए गए हैं। जून 2025 तक देशभर में संचालित फीडिंग रूम्स की कुल संख्या 502 है। ब्रांड द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक फीडिंग रूम का प्रतिदिन औसतन 30 माताएं उपयोग करती है, जो दर्शाता है कि ऐसी सुविधाओं की निरंतर मांग बनी हुई है।

इस तरह हर वर्ष 55 लाख से अधिक माताएं हिमालया बेबीकेयर द्वारा संवेदनशीलता के साथ डिजाइन किए गए इन माताओं के अनुकुल मातृ-हितैषी फीडिंग स्पेस से लाभान्वित हो रही हैं, जिससे उन्हें देशभर में स्वच्छ और निजी स्तनपान सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो रही हैं।

इस पहल पर टिप्पणी करते हुए हिमालया वेलनेस कंपनी के बेबीकेयर डिवीजन के निदेशक, श्री चक्रवर्ती एन. वी. ने कहा, "हिमालया बेबीकेयर में, शिशुओं और माताओं की देखभाल ही हमारे सभी प्रयासों की प्रेरणा और उद्देश्य है। हमारी ब्रेस्टफीडिंग फैसिलिटी पहल माताओं को, चाहे वे कहीं भी हों, वहां हम उन्हें पूरी संवेदनशीलता और ध्यान के साथ सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये फीडिंग रूम बिना उनकी गतिशीलता या सुविधा से समझौता किए माताओं को वह गोपनीयता प्रदान करते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है।"

यह पहल हिमालया के उस मिशन को दर्शाती है जिसका उद्देश्य प्रत्येक मां और शिशु के लिए सुखद शुरुआत सुनिश्चित करना है। साथ ही, यह शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में माता-पिता के रोजमर्रा के अनुभवों को समझते हुए एक सकारात्मक और सार्थक सामाजिक बदलाव को भी बढ़ावा देती है।

अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को मजबूत ब्रांड उद्देश्य के साथ जोड़कर, हिमालया बेबीकेयर एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर है, जहां मातृत्व से जुड़ी सुविधा और देखभाल केवल समर्थन तक सीमित न हो, बल्कि प्राथमिकता बन जाए।

लोकायुक्त का खुलासा, भाजपा के पूर्व मेयर जय प्रकाश ने डूसिब की जमीन पर बना दी बिल्डिंग- अंकुश नारंग

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने सरकारी जमीन को हड़प कर उस पर अवैध तरीके से बहुमंजिला इमारत बनाने के मामले में भाजपा के पूर्व मेयर जय प्रकाश के खिलाफ आरोप है साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि लोकायुक्त ने इस गंभीर मामले का खुलासा किया है। पूर्व मेयर जय प्रकाश पर आरोप है कि पावर का दुरुपयोग कर पहले प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कराया। इसके बाद उस पर अवैध बहुमंजिला इमारत बना डाली। जबकि डूसिब ने इस प्रॉपर्टी को दो लोगों को लाइसेंस फीस पर दी थी। यह सरकारी जमीन है और इसे कोई ट्रांसफर नहीं करा सकता। निर्माण के दौरान पुलिस से चालान और डूसिब ने अवैध निर्माण की नोटिस भी दी थी। इसके बाद भी बिल्डिंग का निर्माण बंद नहीं हुआ। ''आप'' की मांग है कि इसकी जांच की जाए और पूर्व मेयर जय प्रकाश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

आम आदमी पार्टी के एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर कहा कि जय प्रकाश भाजपा के बड़े नेता हैं और वह दिल्ली के महापौर भी रह चुके हैं। लोकायुक्त की रिपोर्ट में जय प्रकाश पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के सदर बाजार के बहादुर गढ़ मार्ग पर स्थित 3231/13, गली विक्रम की प्रॉपटी डूसिब की है। भाजपा नेता जय प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से हड़प लिया और इस पर अवैध निर्माण भी कर लिया। कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। आरोप है कि जय प्रकाश ने इस सरकारी प्रॉपर्टी को अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर करवाया, जबकि नियमानुसार यह ट्रांसफर नहीं हो सकती थी।

उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। इसलिए जय प्रकाश ने यह दिखाया कि जिनके पास यह प्रॉपर्टी लाइसेंस पर थी, उनसे उन्होंने इसे खरीद ली है। इस मामले को लेकर एक व्यक्ति लोकायुक्त में शिकायत की। केस में यह साफ तौर पर दर्शाया गया है कि जब जय प्रकाश महापौर थे, तब उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके इस प्रॉपर्टी को खरीदा। जय प्रकाश ने अवैध तरीके से प्रॉपर्टी को खरीदने के साथ ही उस पर बहुमंजिला बिल्डिंग भी बना दी। प्रॉपर्टी का कुछ हिससा व्यवसायिक और कुछ आवासीय उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोप है कि जय प्रकाश ने अवैध रूप से बिजली के मीटर भी लगवाए और निर्माण किया है।

अंकुश नारंग ने कहा कि उस दौरान डूसिब ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने जय प्रकाश को यह प्रॉपर्टी नहीं बेची है। डूसिब ने यह भी कहा कि उसने दो व्यक्तियों को यह प्रॉपर्टी लाइसेंस फीस पर दी थी और लाइसेंस फीस से यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। डूसिब की रिपोर्ट पर लोकायुक्त ने अब आदेश दिया है कि इस प्रॉपर्टी पर उचित कार्रवाई की जाए। लोकायुक्त ने उपराज्यपाल से कहा है कि पूर्व महापौर और एमसीडी पार्षद जय प्रकाश के खिलाफ पुलिस, एसीबी या अन्य एजेंसियों की जांच के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाए। इस प्रॉपर्टी पर निर्माण के दौरान दिल्ली पुलिस ने चालान भी किया है और डूसिब ने भी सेक्शन 41 के तहत नोटिस भेजा कि यह अवैध निर्माण है। डूसिब की प्रॉपर्टी पर निर्माण नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने ने कहा कि लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर भाजपा के पूर्व मेयर जय प्रकाश पर लगे आरोप के खिलाफ उचित जांच होनी चाहिए। यह पता लगना चाहिए कि डूसिब की प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हुई और उस पर बहुमंजिला इमारत कैसे बन गई? तुरंत जांच शुरू होनी चाहिए और इसके नतीजों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी नेता, महापौर, उपमहापौर या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर अवैध कब्जा या निर्माण न करे। चूंकि आज भी एमसीडी पर भाजपा का कब्जा है। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भी ऐसी गैरकानूनी गतिविधि न हो। हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी तफ्तीश हो और सख्त कार्रवाई हो।

मुस्कान क्लब की अध्यक्ष ने उदारता पूर्वक फन वे लर्निंग एनजीओ को एक व्हीलचेयर दान की। काउंसलर रामिंदर मैडम और पूर्व विधायक जगदीप सर ने भी अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

जंगल ने तुम्हें सलाम भेजा है : मुकेश चंद्राकर के लिए पूनम वासम की चिट्ठी

प्रिय मुकेश,

तुम्हारे रास्ते के सारे फूल मुरझा गए, तुम्हारे हिस्से की सारी नदियां सूख गईं, सारे पहाड़ भरभराकर गिर गए, तुम्हारे हिस्से का सारा दुःख बादल बनकर उड़ गया। सरई के वृक्ष झुककर तुम्हें जोहार कर रहे हैं, चिड़ियों का एक झुंड उड़कर अभी-अभी तुम्हारे घर की मुंडेर पर आया है, उनके हाथों जंगल ने तुम्हें सलाम भेजा है।

एक हिरन दूर खड़ा तुम्हें पुकार रहा है, उसकी रुदन से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। बालीफूल जैसी कितनी ही वन कन्याएं तुम्हारे लिए रास्ते में लाल हजारी के फूल लिए खड़ी हैं। तुम्हारे घर पर यह जो अपराजिता की बेल तुमने लगा रखी है, जाने कब से तुम्हारी राह देख रही है, तुमने जाने कितने गुलाब के पौधे गमलों में लगा रखें हैं, देखो उनकी सारी पत्तियां सूख गई हैं।

तुम्हारे कपड़े अभी भी हैंगर पर लटके हुए हैं, किचन में चाय का बर्तन चाय की खुशबू से अभी भी महक रहा है, तुम्हारे बिस्तर पर सलवटें अभी भी हैं, सामने के दरवाजे पर जो तुमने वॉल हैंगर लटकाया था, वह हवा में अभी भी लहरा रहा है, कविताओं का जो पोस्टर तुमने सामने की दीवार पर चिपकाया था, उसकी पंक्तियां अब धुंधली दिखाई दे रही हैं। तुमसे प्रेम करने वाले सारे लोग तुम्हें छूकर, चूमकर, देखकर तुम्हारी देह को महसूस कर रहे हैं।

तुम सिर्फ अब एक नाम नहीं, तुम अब एक भावना में बदल चुके हो, जो इस वक्त हम सबके भीतर उमड़-घुमड़ रही है। तुम जाने की जिद्द कर रहे हो और हम हैं कि तुम्हें कसकर पकड़े हुए हैं, तुम्हें जाने भी दें तो कैसे जाने दें, भाई मेरे? तुम्हारे जाने से हमारे मन का कोना बाद में खाली होगा, पहले खाली होगा जंगल, फिर जंगल की स्त्रियों का मन, उनकी आंखों की चमक, जिनमें तुमने न्याय का रंग भरा है, उन बच्चों का मन, जिनके भीतर उम्मीद जागी है तुम्हें देखकर कि ₹तुम बनकर जीता जा सकता है जाने कितनों का मन₹ !

जंगल के बच्चे तुम्हारी तरह हाथ में हिम्मत, न्याय और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के हक में अपनी कलम को धार देकर उसे बदल देना चाहते हैं, बोलती हुई, लड़ती हुई, सवाल उठाती हुई, किसी क्रांतिकारी धुन में।

जंगल की स्त्रियां रो रही हैं, वे जानती हैं कि तुम्हारे होने से उनके जीवन में बदलाव का, न्याय का, सम्मान का रंग था, उनकी आंखें तुम्हारी आंखों को ढूंढ रही हैं, ताकि वह दे सकें तुम्हें तुम्हारे अधूरे सपनों की वह पोटली जिसे तुमने उछाल दिया था उस ओर जिस ओर तलवार की नोक बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल दिल वाले हिस्से पर जिसे थोड़ा छूते ही तलवार दिल के आर-पार होता, पर तुम्हें इसकी परवाह कहां थी! तुम्हें परवाह रही है हमेशा उनकी, जिनके हिस्से ना कभी सरकार आई, न कभी सरकार की कोई धमक, न सरकार की कोई योजना। तुम अकेले ही निकले थे उन पगडंडियों पर, जिन पर चलना तलवार की धार पर चलने जितना कठिन था, तुम्हारा साहस, तुम्हारी निश्छलता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा जुनून देखकर तुम्हारे पीछे-पीछे दौड़ने लगा था पूरा का पूरा जंगल।

तुम्हारी निडरता, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा नेक दिल मनुष्य होना ही तुम्हारी कमजोरी बन गई। तुमने सोचा भी नहीं कि यह दुनिया अब वैसी नहीं रही, जैसी तुम बनाना चाहते हो। तुम्हारी मनुष्यता, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी नीयत सब कुछ याद रखा जाएगा भाई मेरे।

अब तुम्हारी याद की महक से यहां की हवाओं को बाहरी संक्रमण से बचाए रखने की हिम्मत हम सब जुटाते रहेंगे।

आंखें नम हैं, पर दिल गर्व से भरा है। तुमने अपनी जिंदगी में जो सच का अलख जगाया, उसकी लौ से बस्तर के आदिवासियों का जीवन, यहां के बच्चों का जीवन, स्त्रियों का जीवन मद्धम-मद्धम रोशन होता रहेगा।इतनी कम उम्र में जो तुमने किया, वह करने में शायद हम जैसे लोगों के लिए पूरी उम्र कम पड़ जाए, तुम्हारी हत्या उन कायरों की जीत नहीं है, यह उनके डर और कमजोरी का प्रमाण है।

तुम्हारी बहन होने का गर्व हमेशा मेरे साथ रहेगा, तुम्हारी लेखनी, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी सोच को मैं हमेशा सहेजकर रखूंगी भईया मेरे।

तुम कहीं नहीं गए हो, तुम हर उस सच में हो, जिसे बोलने की हिम्मत हम तुमसे सीखते रहेंगे, तुम हर उस लड़ाई में हो, जिसे हम तुम्हारी याद में लड़ने की कोशिश में जारी रखेंगे।

तुम्हारे बिना जीवन कठिन है मुकेश, हम सब आधे-अधूरे हैं। जहाँ भी रहो, बस अपनी आवाज में मुझे दिद्दु पुकारते रहना, भूलना मत भईया मेरे।

तुम्हारी दिद्दु
पूनम वासम

(पूनम वासम प्रसिद्ध कवयित्री हैं, जिन्होंने मुकेश चंद्राकर की ओर से 'लोकजतन' सम्मान ग्रहण किया। मुकेश की कॉर्पोरेट ठेकेदारों ने इस वर्ष 1 जनवरी को हत्या कर दी थी।)

सांसद चाहर व भाजपा नेता उपेंद्र सिंह ने नगला कारे के 100 से अधिक दलित परिवारों के आशियाने टूटने से बचाये

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। धनौली क्षेत्र के अंतर्गत मजरा नगला कारे में लगभग 100 से अधिक दलित परिवारों के मकानों को गिराने के आदेश तहसीलदार सदर द्वारा जारी किए गए थे। इस कार्रवाई से गांव में दहशत का माहौल बन गया था। इस मामले का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश कोऑर्डिनेटर (यूपी) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग उपेंद्र सिंह ने लिया। उन्होंने पीड़ित दलित परिवारों को साथ लेकर तत्काल फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर के आवास पर पहुँचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

सांसद चाहर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जिलाधिकारी से बातचीत कर मामले की गंभीरता को रखा। तत्पश्चात अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने तहसीलदार द्वारा जारी तोड़फोड़ आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे सैकड़ों दलित परिवारों के घर टूटने से बच गए। इस न्याय की जीत पर आज नगला कारे में ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत एवं आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम से पूर्व भाजपा नेता उपेन्द्र सिंह बाबा साहेब को नमन कर माल्यार्पण किया। दलित समाज के लोगों ने भाजपा नेता उपेंद्र सिंह का जोशीला स्वागत किया। साथ ही सांसद व भाजपा नेता उपेंद्र सिंह के प्रयासों की सराहना की।

भाजपा नेता उपेंद्र सिंह ने भी इस न्यायिक निर्णय पर सांसद राजकुमार चाहर को फोन कर बधाई व धन्यवाद दिया, और जिलाधिकारी से भेंट कर व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने इसे संविधान में आस्था की जीत बताया और कहा कि संकट की इस घड़ी में सांसद चाहर व भाजपा नेता उपेंद्र सिंह की तत्परता ने हमें न्याय दिलाया।

वही उपेन्द्र सिंह ने पीड़ति दलित परिवार के मकानों के निरीक्षण किया। कार्यक्रम का संचालन सोमदत्त ने किया।

इस अवसर पर प्रधानपति लोकेश सिंह, नेत्रपाल सिंह , गौरव वाल्मीकि, पंडित तुलाराम शर्मा, तेज कपूर, ताराचंद,जितेंद्र कुमार, मनीष सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

भागवत पीठ में सप्त दिवसीय 28वां श्रावण झूलन भागवत महोत्सव 26 जुलाई से

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। रुक्मिणी विहार रोड़ (निकट केशव धाम) स्थित भागवत पीठ आश्रम में सत्य सनातन सेवार्थ संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट, वृन्दावन के द्वारा श्रावण मास के पावन अवसर पर सप्तदिवसीय 28वां श्रावण झूलन भागवत महोत्सव 26 जुलाई से 01 अगस्त 2025 पर्यंत अत्यंत श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। जानकारी देते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने बताया है कि महोत्सव का शुभारंभ 26 जुलाई को प्रातः 8:30 बजे गाजे-बाजे के मध्य निकलने वाली भव्य कलश यात्रा के साथ होगा।तदोपरान्त 09 से 01 बजे तक विश्वविख्यात भागवत प्रवक्ता एवं भागवत/आचार्य पीठाधीश्वर वैष्णवाचार्य मारुतिनंदनाचार्य ₹वागीशजी₹ महाराज अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा श्रीमद्भागवत कथा की अमृत वर्षा कराएंगे।

युवराज श्रीधराचार्य महाराज ने बताया कि महोत्सव के अंतर्गत 27 जुलाई को सायं 06 से 07:30 बजे तक योगाचार्य राजेश अग्रवाल के द्वारा हास्य योग किया जाएगा। 29 जुलाई को सायं 06 बजे से श्रीहनुमत आराधन मंडल के द्वारा सुन्दरकाण्ड का सामूहिक सस्वर पाठ होगा।इसके अलावा रुद्राभिषेक, तुलसी सहस्त्रार्चन, तीज महोत्सव एवं हिंडोला उत्सव आदि कार्यक्रम भी संपन्न होंगे।जिसमें सभी भक्त-श्रद्धालु सादर आमंत्रित हैं।

शैलेन्द्र शैली स्मृति व्याख्यानमाला में बोले उर्मिलेश : अंबेडकर दलितों के नहीं, मानवता के मसीहा थे ; मुकेश चंद्राकर के लिए पूनम वासम ने ग्रहण किया लोकजतन सम्मान, कनक तिवारी ने भी दिया विचारोत्तेजक वक्तव्य

परिवहन विशेष न्यूज

रायपुर। "बाबा साहेब आंबेडकर दलितों के नहीं, मानवता के मसीहा थे। उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष गांधीजी की सलाह पर बनाया गया था, जबकि गांधीजी और अंबेडकर की वैचारिकी एकदम अलग थी। इसके बावजूद वे दोनों आधुनिक भारत के निर्माण और उसके लोकतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष भविष्य के बारे में साझा दृष्टिकोण रखते थे। आंबेडकर के बिना संविधान नहीं बन सकता था। वे बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन वह संभव नहीं था, क्योंकि संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था। इसके बावजूद आंबेडकर ने एक शानदार संविधान दिया। इस संविधान और इसके बुनियादी मूल्यों की रक्षा करना आज सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि आज केंद्र की सत्ता में जो पार्टी है, वह इन मूल्यों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मूल्य हमारी स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई के दौरान विकसित हुए थे और संघ-भाजपा न केवल इस लड़ाई से दूर थी, बल्कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद की समर्थक ही थी।"

उक्त विचार वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने कल शैलेन्द्र शैली स्मृति व्याख्यान माला में ₹लोकतांत्रिक भारत में पत्रकारिता की चुनौतियां₹ विषय पर बोलते हुए रखे। उन्होंने कहा कि हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए समझौता और संघर्ष की रणनीति अपनाई। यह हमारी आजादी की लड़ाई का यूनिक फीचर था। इसी संघर्ष के दौरान धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, सामाजिक न्याय, भाईचारे की आधुनिक अवधारणा का विकास हुआ, जिसे हमारे संविधान में समाहित किया गया। उन्होंने संघ भाजपा के इस दुष्प्रचार का कड़ा प्रतिवाद किया कि हमारे मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख नहीं था और संविधान के अनुच्छेद 25 (2) (ए) का हवाला देते हुए बताया कि हमारा संविधान किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं करता।

उर्मिलेश ने कहा कि बाबा साहेब ने साफ साफ कहा था कि यदि संविधान को क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे होंगे, तो यह संविधान भी बुरा ही साबित होगा। आज जो लोग सत्ता में हैं, वे आज इस संविधान के रहते ही आम जनता को इसके बुनियादी मूल्यों से अलग करने की साजिश रच रहे हैं। जैसे जैसे ये मूल्य कमजोर हो रहे हैं, भारत में लोकतंत्र भी कमजोर हो रहा है और वह लोकतांत्रिक गणराज्य से कॉर्पोरेट राज में बदल रहा है। इसका असर मीडिया और प्रेस पर भी पड़ रहा है। कॉर्पोरेट मीडिया आम जनता के सामने झूठ परोसने का माध्यम बन गया है। वह आरक्षण विरोधी और मंदिर समर्थक हो गया है। उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रवाद वह है, जो जाति और धर्म के ढांचे से बाहर निकलकर देश की जनता को सहनशीलता और सहिष्णुता के आधार पर मोहब्बत करना सीखाता है। लोकतंत्र के इस स्वरूप को मीडिया और समाज में बचाए रखना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती है।

उल्लेखनीय है कि यह व्याख्यान माला 24 जुलाई से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेगी। यह पहला दिन था और इसी दिन देश के किसी पत्रकार को पत्रकारिता में उसके उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकजतन सम्मान से अभिनंदित किया जाता है। इस समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध ने की। इस वर्ष का लोकजतन सम्मान बीजापुर के शहीद पत्रकार मुकेश चंद्राकर को दिया गया, जो छत्तीसगढ़ में कॉरपोरेट विरोधी पत्रकारिता के आइकॉन थे। मुकेश की ओर से यह सम्मान उनकी बहन और प्रसिद्ध कवियित्री पूनम वासम ने ग्रहण किया। इस अवसर पर सम्मान ग्रहण करते हुए उन्होंने मुकेश की मानवीय खूबियों और उसकी पत्रकारिता के गुणों की विशेष चर्चा की तथा उन्हें पूरे समाज का हीरो बताया।

रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने विस्तार से बताया कि एक छोटे से गांव बासेगुड़ा से निकलकर, झंझावातों का सामना करते हुए, सलवा जुडूम आंदोलन के दौर में विस्थापन और उत्पीड़न का शिकार होते हुए किस तरह मुकेश ने पत्रकारिता जगत में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बताया कि अपने जीवंत संपर्कों और संबंधों के आधार पर मुकेश ने कई लोगों को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाया। मुकेश में अकेले संघर्ष करने का माद्दा भी था और वे किसी भी सही मुद्दे पर अकेले धरने पर भी बैठ सकते थे। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की चुनौती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की तरह इस सरकार में भी पत्रकारों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, जो दुर्भाग्यजनक है।

वरिष्ठ अधिवक्ता, लेखक और संविधान विशेषज्ञ कनक तिवारी ने भी इस अवसर पर विचारोत्तेजक वक्तव्य दिया। उन्होंने स्वयं को गांधीवादी-वामपंथी और कॉमरेड बताते हुए कहा कि संविधान में ₹हम भारत के लोग₹ संप्रभु हैं, न कि कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य कोई अधिकारी। यह आंबेडकर ही थे, जिन्होंने प्रेस की आजादी को नागरिक आजादी से जोड़ा और उन्होंने ही देश को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान प्रेस ने बड़ी कुर्बानियां दी थीं और उस समय गांधीजी सबसे बड़े पत्रकार थे।आज इस पत्रकारिता पर जो खतरा है, वह अजीत अंजुम और हेमंत मालवीय पर हो रहे हमलों के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र और अंबेडकर के संविधान की रक्षा करके ही जन पक्षधर पत्रकारिता को बचाया जा सकता है।

वरिष्ठ फोटो पत्रकार विनय शर्मा के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने और सुदीप ठाकुर, रमेश अनुपम, कमल शुक्ल, सुधीर तंबोली और अरविंद आदि के द्वारा अतिथियों के सम्मान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत में लोकजतन के संपादक बादल सरोज ने इसके संस्थापक संस्थापक शैलेन्द्र शैली के देश की राजनीति और जन आंदोलनों को संगठित करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सामने रखते हुए इस सम्मान और व्याख्यान माला के महत्व का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि मुकेश चंद्राकर वो जुगनू थे, जिनमें घोर अंधकार को तिरोहित करने की क्षमता थी। उनकी शहादत का सम्मान करते हुए लोकजतन स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा है। इस अंधकारपूर्ण दौर में लोकजतन भी जुगनू का ही काम कर रहा है। जनवादी लेखक संघ के राज्य सचिव पूर्णचंद्र रथ ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया। इस अवसर पर मुकेश चंद्राकर के सहयोग से और रौनक शिवहरे तथा प्रसून गोस्वामी के निर्देशन में बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।

अभी तक डॉ. राम विद्रोही (ग्वालियर), कमल शुक्ला (बस्तर-रायपुर), लज्जाशंकर हरदेनिया (भोपाल), अनुराग द्वारी (भोपाल), राकेश अचल (ग्वालियर), पलाश सुरजन (भोपाल) आदि प्रमुख पत्रकारों को इस सम्मान से अभिनंदित किया जा चुका है। लोकजतन द्वारा रायपुर में पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर, कांकेर, कोरबा से आए पत्रकार और बुद्धिजीवी भारी संख्या में उपस्थित थे।

लोकजतन की ओर से संजय पराते द्वारा जारी

भारत यूके सीईटीए मुनाफेवाली डील पक्की- इकोनॉमी को बूस्टर डोज-टैरिफ टेंशन के खिलाफ संजीवनी बूटी-आर्थिक भगोड़ों का प्रत्यार्पण संभव?

यूरोपीय संघ से बाहर निकालने के बाद ब्रिटेन का भारत के साथ पहला सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी समझौता-4 वर्षों की मेहनत रंग लाई

भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व कारोबारी समझौता (सीईटीए) पक्का-द्विपक्षीय रिश्तो का विज़न डॉक्यूमेंट 2035 क़ा भी ऐतिहासिक करार-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ जानती है कि भारत सहित अनेको देशों पर अंग्रेजों यानें इंग्लैंड का शासन था यानें वे सभी देश गुलामी के साए में जी रहे थे। समय का चक्र ऐसा घूमा कि आज इस देश का प्रधानमंत्री भी एक भारतीय मूल का ऋषि सुनक बना था,तथा आज भी शासकीय प्रशासकीय व सरकार में मूल भारतीयों के अनेकों लोग हैं, जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र, मानता हूं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए ही वह आर्थिक सूची में भारत से पीछे यांने 6 नंबर पर है, व भारत चार नंबर पर है जो शीघ्र ही तीन नंबर पर होने की पूरी पूरी संभावना है। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत व ब्रिटेन के बीच आज 24जुलाई 2025 को व्यापकआर्थिक व्यापार समझौता (सीईटीए) व पारस्परिक दोहरा योगदान संधि (डीईसी) समझौता हुआ है, जिसका लाभ दोनों देशों की इकोनॉमी को एक बूस्टर डोज है, टेंशन के खिलाफ संजीवनी बूटी है,आर्थिक भगोड़ों का प्रत्यार्पण संभव? इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, यूरोपीय संघ से बाहर निकालने के बाद ब्रिटेन का भारत के साथ पहला सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी समझौता-चार वर्षों की मेहनत रंग लाई।

साथियों बात अगर हम भारत और ब्रिटेन के बीच 24 जुलाई 2025 को हुए ऐतिहासिक समझौते की करें तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे वर्षों से चली आ रही लंबी बातचीत का अंत हुआ और उनकी आर्थिक साझेदारी में एक नए चरण की शुरुआत हुई। यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा और प्रमुख क्षेत्रों में बेहतर बाज़ार पहुँच प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौता हो गया है, जिससे आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और 2030 तक व्यापार को 120 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुए इस समझौते पर वाणिज्य मंत्री और उनके ब्रिटिश समकक्ष ने भारतीय और ब्रिटेन के पीएम की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। भारत - ब्रिटेन एफटीए से भारत के लिए प्रमुख आर्थिक लाभ प्राप्त होने का वादा किया गया है, क्योंकि इससे 99 पेर्सेंट भारतीय निर्यात पर टैरिफ समाप्त हो जाएगा, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100 पेर्सेंट होगा।भारतीय व्यवसायों को ब्रिटेन में शून्य- शुल्क पहुँच का लाभ मिलेगा, जिसमें कपड़ा, जूते, कालीन, कार और समुद्री उत्पादों का निर्यात भी शामिल है, जिन पर वर्तमान में 4-16 पेर्सेंट का शुल्क लगता है।ब्रिटेन को भारत में स्कॉच व्हिस्की और प्रीमियम कारों जैसी विलासिता की वस्तुओं पर शुल्क में कमी देखने को मिलेगी। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के पीएम ने आज ऐतिहासिक भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते [सीईटीए] पर हस्ताक्षर के बाद भारत और ब्रिटेन के उद्योगपतियों से मुलाकात की। बैठक में स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रत्न एवं आभूषण, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, विनिर्माण, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, आईटी, लॉजिस्टिक्स, वस्त्र और वित्तीय सेवा क्षेत्रों के दोनों पक्षों के प्रमुख उद्योगपति उपस्थित थे। ये क्षेत्र दोनों देशों में रोजगार सृजनऔर समावेशी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।दोनों नेताओं ने हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में हुए विस्तार का उल्लेख किया। उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए, उन्होंने उन्हें व्यापार,निवेश और नवाचार साझेदारी को गहरा करने के लिए सीईटीए से मिलने वाले अवसरों की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, उन्होंने कहा कि यह नया समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में व्यापारिक भावना को बढ़ावा देगा। सीईटीए के ठोस लाभों पर प्रकाश डालते हुए, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के प्रमुख उत्पादों और नवाचारों की एक प्रभावशाली श्रृंखला प्रदर्शित की। प्रदर्शनियों में रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता उत्पाद और उन्नत तकनीकी समाधान शामिल थे।भारत-ब्रिटेन के उद्योग प्रमुखों ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते की सराहना की और आशा व्यक्त की कि यह व्यापक रणनीतिक साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत करेगा और न केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था में, बल्कि उभरती प्रौद्योगिकियों, शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी सहयोग को गहरा करेगा।दोनों नेताओं ने नए समझौते की क्षमता का दोहन करने और आने वाले वर्षों में आर्थिक सहयोग के बंधनों को गहरा करने के लिए छोटे और बड़े व्यवसायों को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

साथियों बात अगर हम ब्रिटेन के साथ हुए करार के बाद पीएम द्वारा ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की करें तो उन्होंने कहा, भारतीय वस्त्र, जूते, रत्न एवं आभूषण,समुद्री खाद्य और इंजीनियरिंग वस्तुओं को ब्रिटेन के बाज़ार में बेहतर पहुँच मिलेगी। ब्रिटिश बाज़ार में भारत के कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के लिए भी नए अवसर खुलेंगे।यह समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। साथ ही, ब्रिटेन में बने उत्पाद—जैसे चिकित्सा उपकरण और एयरोस्पेस पुर्जे-भारतीय उपभोक्ताओं और उद्योग के लिए अधिक सुलभ और किफायती हो जाएँगे।भारत-ब्रिटेन एफटीए में इस स्तर पर कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) - तथाकथित कार्बन कर - शामिल नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों ने कहा कि इस पर बाद में चर्चा की जाएगी।भारत और ब्रिटेन अगले दशक में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में 'विजन 2035' कार्यक्रम पर भी चर्चा करेंगे। सरकार द्वारा एफटीए एजेंडे को गति देने के बाद से किसी विकसित पश्चिमी अर्थव्यवस्था के साथ भारत का पहला बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, जो निर्यात बाजारों में विविधता लाने और निवेश आकर्षित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

साथियों बात अगर हम इस सीईटीए करार से किसानों मजदूरों एमएसएमई मध्यवर्गीय व व्यापार जगत को फायदा होने की करें तो, प्रमुख क्षेत्रों में बड़ी बढ़त भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत- यूके एफटीए से भारतीय किसानों को यूके के 37.5 बिलियन डॉलर के कृषि बाजार तक तरजीही पहुंच मिलेगी, जबकि डेयरी, सब्जियां, सेब, खाना पकाने के तेल और जई जैसे संवेदनशील भारतीय क्षेत्रों की रक्षा होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय मछुआरों के लिए एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि समुद्री उत्पादों पर ब्रिटेन का आयात शुल्क - जो वर्तमान में 20 पेर्सेंट तक है - शून्य हो जाएगा, जिससे 5.4 बिलियन डॉलर का बाजार खुल जाएगा।मंत्रालय ने बयान में कहा कि श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोज़गार सृजन में तेज़ी आने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय निर्यात ब्रिटेन में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल कर रहा है। बयान में कहा गया है कि कपड़ा और परिधान, रसायन और मूल धातुओं पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा,जो पहले क्रमशः12 पेर्सेंट 8 पेर्सेंट और 10 पेर्सेंट तक के टैरिफ से कम होगा।स्कॉच व्हिस्की पर सीमा शुल्क में प्रस्तावित कटौती - 150 पेर्सेंट से 75 पेर्सेंट तक, तथा उसके बाद 5 पेर्सेंट वार्षिक कटौती होंगी इस क्षेत्र से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा इससे उत्पादकों के मार्जिन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे भारतीय व्हिस्की बाजार में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना नहीं है।उन्होंने कहा,आयातित स्कॉच की उपभोक्ता कीमतों में कोई खास गिरावट आने की उम्मीद नहीं है क्योंकि शराब पर लगने वाले कर का बड़ा हिस्सा राज्यों के पास है। अगर पूरी शुल्क कटौती लागू भी कर दी जाए, तो भी इससे कीमतों में प्रति बोतल केवल ₹ 100-300 की कमी आएगी—जो नए खरीदारों को आकर्षित करने के लिए बहुत कम है। भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता ब्रिटेन के साथ परिधान व्यापार के एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह समझौता बाज़ार पहुँच बढ़ाएगा, परिधान क्षेत्र में निवेश और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देगा, साथ ही दोनों पक्षों के व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा।यह किसी विकसित पश्चिमी अर्थव्यवस्था के साथ भारत का पहला बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, जो निर्यात बाजारों में विविधता लाने और निवेश आकर्षित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।इसके अलावा, भारत और ब्रिटेन ने दोहरे अंशदान समझौते (डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन) नामक एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर बातचीत पूरी कर ली है। इसके तहत, ब्रिटेन में भारतीय कामगारों और नियोक्ताओं को तीन साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी, जिससे लगभग 75,000 भारतीय कामगारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।इस समझौते से भारतीय पेशेवरों की गतिशीलता में भी सुधार होगा, जिससे 1,800 शेफ, योग प्रशिक्षक और शास्त्रीय संगीतकार अस्थायी रूप से ब्रिटेन में सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। भारत-यूके एफटीए से भारतीय किसानों को यूके के 37.5 बिलियन डॉलर के कृषि बाजार तक तरजीही पहुंच मिलेगी, जबकि डेयरी, सब्जियां, सेब, खाना पकाने के तेल और जई जैसे संवेदनशील भारतीय क्षेत्रों की रक्षा होगी।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत यूके सीईटीए मुनाफेवाली डील पक्की- इकोनॉमी को बूस्टर डोज- टैरिफ टेंशन के खिलाफ संजीवनी बूटी- आर्थिक भगोड़ों का प्रत्यार्पण संभव?यूरोपीय संघ से बाहर निकालने के बाद ब्रिटेन का भारत के साथ पहला सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी समझौता- 4 वर्षों की मेहनत रंग लाई भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व कारोबारी समझौता (सीईटीए) पक्का-द्विपक्षीय रिश्तो का विज़न डॉक्यूमेंट 2035 क़ा भी ऐतिहासिक करार।

नई हीरो ग्लैमर 125 भारत में जल्द होगी लॉन्च, क्रूज कंट्रोल समेत मिलेंगे कई राइडिंग मोड

परिवहन विशेष न्यूज

नई Hero Glamour 125 जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली है। यह अपने सेगमेंट की पहली बाइक होगी जिसमें क्रूज कंट्रोल फीचर मिलेगा। राइड-बाय-वायर थ्रॉटल और नया TFT कंसोल जैसे फीचर्स भी इसमें शामिल होंगे। हीरो ग्लैमर 125 में 124 .7cc का इंजन होगा। इसे अक्टूबर 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है और इसकी अनुमानित कीमत 92 हजार रुपये से 98 हजार रुपये के बीच होगी।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में जल्द ही अपडेटेड Hero Glamour 125 लॉन्च होने वाली है। इसे कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लाया जाना वाला है। यह अपने सेगमेंट की पहली बाइक होगी, जिसमें क्रूज कंट्रोल मिलेगा। इतना ही नहीं और भी कई बदलाव के साथ हीरो ग्लैमर 125 को लॉन्च किया जाएगा। आइए विस्तार में जानते हैं कि हीरो ग्लैमर 125 को किन खास नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा?

क्या मिलेगा नया?

नई Hero Glamour 125 में क्रूज कंट्रोल के साथ नए इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल (राइड-बाय-वायर थ्रॉटल), ज्यादा प्रीमियम दिखने वाले स्विचगियर, नया TFT कंसोल दिया जा सकता है। इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल फीचर मिलने से इसे फीजिकल थ्रॉटल केबल के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंट्रोल किया जा सकेगा। यह थ्रॉटल को एक स्विच के जरिए से भी एक निश्चित सीमा तक कंट्रोल करने देगा और इस तरह से बाइक में क्रूज कंट्रोल फीचर मिलेगा। इसे बाइक में देने के पीछे की वजह लंबी दूरी के सफर के दौरान राइडर की राइड को आरामदायक बनाना है। क्रूज कंट्रोल को दाहिने हाथ के स्विचगियर पर मिलेगा।

इसमें कई राइडिंग मोड्स भी दिए जा सकते है। TVS Raider 125 के बाद यह राइडिंग मोड्स वाली भारत की दूसरी 125cc बाइक होगी। इसमें नया TFT कंसोल दिया जा सकता है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ-साथ अन्य कनेक्टेड फीचर्स मिल सकते हैं। इसमें एलईडी इंडिकेटर भी मिलेंगे।

इस बाइक को Glamour लाइनअप में दूसरे वेरिएंट से अलग दिखाने के लिए डिजाइन में हल्का बदलाव भी दिया जा सकता है। इसके तहत इसके फ्यूल टैंक को रिडिजाइन किया जा सकता है। इसे ज्यादा प्रीमियम कलर स्कीम के साथ लाया जा सकता है।

क्या होगा नाम?

इसका नाम Hero Glamour Xtec 2.0 हो सकता है और इसे ग्लैमर लाइनअप में टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट के रूप में पेश किया जाएगा। दरअसल, हीरो पहले से ही टॉप-एंड Splendor Plus Xtec 2.0 को पेश करती है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि नई बाइक का नाम Hero Glamour Xtec 2.0 हो सकता है

इंजन हो सकता है पहले जैसा

नई Hero Glamour 125 के इंजन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसमें वही 124.7cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिए जाने की संभावना है, जो 10.7 PS की पावर और 10.6 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा।

भारत में कब होगी लॉन्च?

नई Hero Glamour 125 को भारतीय बाजार में फेस्टिव सीजन अक्टूबर 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 92 हजार रुपये से 98 हजार रुपये के बीच होने की उम्मीद है।

कहीं आपकी गाड़ी का बीमा फर्जी तो नहीं? दिल्ली में 80,000 नकली पॉलिसियां पकड़ी गईं

ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी का बीमा कराते वक्त शर्तें और डिटेल्स ठीक से नहीं पढ़ते। लेकिन अब यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन इंश्योरेंस फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है।

ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी का बीमा कराते वक्त शर्तें और डिटेल्स ठीक से नहीं पढ़ते। लेकिन अब यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन इंश्योरेंस फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है। जिसमें 80,000 से ज्यादा फर्जी पॉलिसियां जारी की गई थीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह फर्जीवाड़ा खास तौर पर दो-पहिया वाहन चालकों के साथ हुआ, जिन्हें तीन और चार-पहिया वाहनों की पॉलिसियां बेच दी गईं, वो भी ज्यादा प्रीमियम लेकर।

इस घोटाले का पता मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) (एमएसीटी) को तब चला जब उन्होंने अपने आंतरिक ऑडिट में डेटा में गड़बड़ी देखी और बीमा कंपनी को नोटिस भेजना शुरू किया।

बीमा घोटाला कैसे हुआ

फिलहाल क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार, फ्रॉड करने वालों ने बीमा वेबसाइट को हैक कर लिया था। उन्होंने पोर्टल के मेनू ऑप्शन से लेकर डेटा तक सब कुछ बदल डाला, और पॉलिसियों की प्रीमियम रकम को भी मनमाने तरीके से बढ़ा दिया। दिल्ली में ऐसे कम से कम 5,000 वाहनों को नकली बीमा दिया गया है, जिन्हें अब अमान्य घोषित कर दिया गया है।

बीमा कंपनी के एक प्रतिनिधि ने मीडिया से बातचीत में बताया कि धोखेबाजों ने ग्राहकों की सारी जानकारी, गाड़ी की कैटेगरी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदल दीं। उन्होंने देशभर से गाड़ियों की बीमा डिटेल्स जुटाईं, उसमें हेरफेर की और फिर जानी-मानी कंपनियों के नाम पर नकली पॉलिसियां बेच दीं। दो-पहिया वाहन मालिकों को तीन-पहिया और चार-पहिया वाहनों की पॉलिसियां बेचकर उनसे ज्यादा पैसा वसूला गया।

होंडा CB125 हॉर्नेट वर्सेज हीरो एक्स्ट्रीम 125R: इंजन, परफॉर्मेंस और फीचर्स के मामले में कौन बेस्ट?

परिवहन विशेष न्यूज

Honda CB125 Hornet vs Hero Xtreme 125R होंडा टू-व्हीलर ने भारतीय बाजार में Honda CB125 Hornet लॉन्च की है जो Hero Xtreme 125R को टक्कर देगी। Hornet में 123 .94cc का इंजन है जबकि Xtreme 125R में 124 .7cc का इंजन है। Hornet हल्की है और इसमें बेहतर फीचर्स हैं वहीं Xtreme 125R में ABS और i3s तकनीक है। Hornet में TFT स्क्रीन और Xtreme में LCD कंसोल है।

नई दिल्ली। होंडा टू-व्हीलर ने भारतीय बाजार में प्रीमियम 125cc स्ट्रीटफाइटर सेगमेंट में कदम रखते हुए Honda CB125 Hornet को लॉन्च किया है। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला Hero Xtreme 125R को सीधी टक्कर देते हुए दिखाई देगी। Xtreme 125R ने अपने सेगमेंट में एक पावरफुल और स्टाइलिश ऑप्शन के रूप में स्थापिक कर लिया है। दोनों ही मोटरसाइकिल बेहतर परफॉर्मेंस, शानदार डिजाइन और जबरदस्त फीचर्स के साथ आती है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको इन दोनों बाइक (Honda CB125 Hornet vs Hero Xtreme 125R) की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन बेहतर है?

Honda CB125 Hornet में 123.94cc, 1-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, 2-वाल्व इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसका इंजन 11.14 PS की पावर और 11.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

Hero Xtreme 125R में 124.7cc 1-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, 2-वाल्व इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लगा हुआ इंजन 11.56 PS की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

Honda CB125 Hornet vs Hero Xtreme 125R: अंडरपिनिंग्स

Honda CB125 Hornet में गोल्डन कलर का इनवर्टेड फोर्क दिया गया है, जो इस सेगमेंट की किसी बाइक में पहली बार दिया गया है। Hero Xtreme 125R में बड़ी फ्रंट डिस्क दी गई है, जिसके ABS वेरिएंट पर 276mm के साथ बेहतर ब्रेकिंग देती है। दोनों ही बाइक में एक मोनोशॉक दिया गया है। Xtreme के मोटा टायर दिया गया है, जिसकी वजह से यह ज्यादा मस्कुलर लगती है।

CB125 Hornet, Xtreme 125R के मुकाबले 8-12kg हल्की है, जिसकी वजह से यह ट्रैफिक में ज्यादा फुर्तीली हो सकती है। इसकी सीट की ऊंचाई अच्छी है, Hornet का ग्राउंड क्लीयरेंस Xtreme की तुलना में बहुत कम है। छोटे राइडर्स को Hornet को संभालना आसान लग सकता है, जबकि लंबे राइडर्स Xtreme को ज्यादा पसंद आ सकती है।

टाटा पंच सीएनजी के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की अग्रिम भुगतान के बाद कितनी जाएगी ईएमआई

कार वित्त योजना भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में Tata Punch CNG को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में सबसे सस्ती एसयूवी के तौर पर Tata Punch को ऑफर किया जाता है। Tata की इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Tata Punch CNG Price

टाटा मोटर्स की ओर से पंच एसयूवी को पेट्रोल के साथ ही सीएनजी इंजन के साथ भी ऑफर किया जाता है। CNG इंजन वाले बेस वेरिएंट के तौर पर Pure की बिक्री की जाती है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 7.30 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो 7.30 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 58 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन टैक्स, करीब 35 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 8.23 लाख रुपये हो जाती है।

दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

अगर Tata Punch के CNG इंजन वाले बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 6.23 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 6.23 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 10029 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Car

अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 6.23 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 10029 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Tata Punch CNG के बेस वेरिएंट के लिए करीब 2.19 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 10.42 लाख रुपये हो जाएगी।

किनसे होता है मुकाबला

Tata की ओर से Punch को माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Nissan Magnite, Renault Kiger, Hyundai Exter जैसी एसयूवी के साथ होता है।

महिंद्रा BE 6 और XEV 9e के जल्द आएंगे 4 नए वेरिएंट, कई बेहतरीन फीचर्स से होंगे लैस

Mahindra BE 6 और XUV 9e भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए लोकप्रिय हो रही हैं। कंपनी अब पैक थ्री और पैक थ्री सेलेक्ट ट्रिम स्तरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चार नए वेरिएंट पेश करने की योजना बना रही है। लीक हुए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि ये नए वेरिएंट विभिन्न बैटरी विकल्पों के साथ आएंगे जिसमें 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक शामिल हैं।

नईदिल्ली। Mahindra BE 6 और XEV 9e भारकतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद से लोगों की पसंदीदा इलेक्ट्रिक कार बनती जा रही है। इसे कई बेहतरीन और शानदार फीचर्स के साथ लेकर आया गया है। हाल ही में कंपनी ने इन दोनों के वेरिएंट लाइनअप को Pack Two B79 के साथ बढ़ाया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर इसका होमोलोगेशन डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, जिससे पता चलता है कि महिंद्रा अपनी वेरिएंट लाइनअप को बढ़ाने जा रही है।

आएंगे चार नए वेरिएंट

Mahindra BE 6 और XEV 9e के Pack Two B79 वेरिएंट लॉन्च होने के बाद कंपनी इसके वेरिएंट लाइनअप को और बढ़ाने जा रही है। इस बार कंपनी ने पैक थ्री और पैक थ्री सेलेक्ट ट्रिम लेवल पर ध्यान दे रही है, ताकि ज्यादा बैटरी ऑप्शन के साथ इसे और भी कई वेरिएंट के साथ पेश किया जा सकते हैं। इसके तहत कंपनी इसे चार नए वेरिएंट लाने की तैयारी कर रही है।

BE 6 और XUV 9e पैक टू ट्रिम को जब लॉन्च किया गया था, तब इसमें केवल 59 kWh बैटरी पैक दिया गया था। ग्राहकों की मांग को देखते हुए कंपनी ने हाल ही में पैक टू को एक बड़ी 79 kWh बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया। अब इसी तरह से BE 6 और XUV 9e के नए वेरिएंट लानी की तैयारी कंपनी कर रही है।

BE 6 और XUV 9e के नए वेरिएंट को लेकर लीक हुए डॉक्यूमेंट के अनुसार, महिंद्रा ने BE 6 और XUV 9e के पैक थ्री और पैक थ्री सेलेक्ट ट्रिम लेवल के ज्यादा वेरिएंट बनाए हैं। जब BE 6 और XUV e का पैक थ्री सेलेक्ट ट्रिम लॉन्च किया गया था, तब इसमें केवल 59 kWh बैटरी दिया गया था और BE 6 और XUV 9e के टॉप-स्पेक पैक थ्री में केवल एक बड़ी 79 kWh बैटरी पैक मिलती थी।

कहां फिट होंगो नए वेरिएंट?

जल्द ही BE 6 और XUV 9e को पैक थ्री सेलेक्ट B79 (79 kWh बैटरी) और पैक थ्री B59 (59 kWh बैटरी) वेरिएंट मिलेंगे। इसका मतलब है कि पैक थ्री सेलेक्ट ट्रिम को एक बड़ी 79 kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा, जो 656 किमी तक की रेंज देगा और और पैक थ्री ट्रिम को एक छोटी 59 kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा।

मोदी की मालदीव यात्रा से हिंद महासागर में फिर मज़बूत हुई भारत की पकड़, चीन की बेचैनी बढ़ी

नीरज कुमार दुबे

मोदी की मालदीव यात्रा से पड़ने वाले असर को देखें तो इस ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब भी मालदीव की रणनीतिक प्राथमिकता है। साथ ही श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी भी देख रहे हैं कि भारत बिना धमकाए, बिना ऋणजाल के, सहयोग और स्थिरता का मार्ग प्रस्तुत करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा केवल एक औपचारिक राजकीय दौरा नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक बिसात पर भारत की चतुर कूटनीति, रणनीतिक धैर्य और नेतृत्व क्षमता का स्पष्ट प्रदर्शन भी है। यह यात्रा इस प्रश्न का उत्तर भी है— कि कैसे भारत ने 'चीन की गोद में जाते' मालदीव को फिर से अपने पक्ष में मोड़ लिया।

हम आपको याद दिला दें कि 2023 में जब मोहम्मद मुइज्जू सत्ता में आए, तो उन्होंने खुलकर ₹India Out₹ अभियान का समर्थन किया और भारतीय सैन्य उपस्थिति पर सवाल उठाए। उनकी शुरुआती विदेश यात्राएं भी संकेत दे रही थीं कि मालदीव अब चीन के करीब जा रहा है। लेकिन भारत ने जल्दबाज़ी में कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। इसके विपरीत, उसने ₹Engagement over Escalation₹ (संवाद, न कि टकराव) की नीति अपनाई। भारत ने रक्षा कर्मियों को तकनीकी विशेषज्ञों से बदला, जिससे मालदीव की 'संप्रभुता' की चिंता को दूर किया गया, लेकिन रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखी गई। साथ ही विकास परियोजनाओं को बिना शोर के आगे बढ़ाया गया जिससे आम जनता को भारत की भूमिका का सकारात्मक प्रभाव दिखता रहा। इसके अलावा, आर्थिक मदद जैसे 30 अरब रुपये की ऋण सुविधा, करेंसी स्वैप और ट्रेजरी बिलों से मालदीव की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा दिया गया। साथ ही सांस्कृतिक, राजनीतिक और पार्टी-स्तरीय जुड़ाव को फिर से शुरू किया गया, जिससे भारत और मालदीव के बीच बहुस्तरीय संपर्क बने रहें।

इसके अलावा, 2024–25 में भारत ने नई परियोजनाएं घोषित करने की बजाय पूर्ववर्ती विकास कार्यक्रमों को तेज़ी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। हनीमाधू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे विशाल निर्माण कार्य इसके उदाहरण हैं। इनका न केवल आर्थिक, बल्कि रणनीतिक महत्व भी है क्योंकि ये चीन समर्थित बंदरगाह-राजनीति के विकल्प प्रस्तुत करते हैं।

देखा जाये तो भारत की नीति में ज़बरदस्त कूटनीतिक परिपक्वता थी। भारत ने मुइज्जू की ओर से उकसाने के बावजूद भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक सोच के साथ अपने कदम आगे बढ़ाये। प्रधानमंत्री मोदी जब मालदीव पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए उमड़ी जनता और अगवानी के लिए पहुँचे मुइज्जू की खुशी देखने लायक थी। हम आपको बता दें कि मालदीव जैसे राष्ट्र में यह परंपरा नहीं रही कि राष्ट्रपति स्वयं एयरपोर्ट पर किसी राष्ट्राध्यक्ष की अगवानी करें। मुइज्जू का प्रधानमंत्री मोदी को हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत रूप से रिसीव करना कई गहरे संदेश देता है। जैसे- यह 'India Out' अभियान से पूरी तरह यू-टर्न है। अब राष्ट्रपति खुद भारत के सर्वोच्च नेता के स्वागत में खड़े हैं। इसके अलावा, मुइज्जू यह दिखाना चाहते हैं कि अब भारत के साथ सहयोग राष्ट्रहित में है। यह संकेत देशवासियों के लिए है कि भारत शत्रु नहीं, सहायक है। यह कूटनीतिक संकेत भी है कि भारत, अब भी मालदीव की विदेश नीति में सर्वोपरि है, चाहे चीन ने कितनी भी कोशिश की हो।

इसके अलावा, मालदीव की राजधानी माले में, भारत की मदद से बने रक्षा मंत्रालय भवन पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर प्रदर्शित होना भी अपने आप में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह न केवल भारत की रक्षा सहायता की स्थायित्व को दर्शाता है, बल्कि यह मालदीव की जनता को दिखाता है कि चीन कर्ज देता है लेकिन भारत सुरक्षा और स्थिरता देता है। देखा जाये तो यह भारत की Soft Power की जीत है, जो किसी भी सैन्य हथियार या बंदरगाह समझौते से अधिक प्रभावशाली साबित हुई है।

मोदी की मालदीव यात्रा से पड़ने वाले असर को देखें तो इसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब भी मालदीव की रणनीतिक प्राथमिकता है। साथ ही श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी भी देख रहे हैं कि भारत बिना धमकाए, बिना ऋणजाल के, सहयोग और स्थिरता का मार्ग प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, मालदीव की भौगोलिक स्थिति हिंद महासागर की व्यापक सामरिक निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी की यात्रा के बाद भारत की मौजूदगी और वैधता वहाँ स्थिर और वैधानिक हो गई है— यह चीन के लिए एक रणनीतिक अवरोध है।

हम आपको बता दें कि यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री गैर-MDP सरकार द्वारा आमंत्रित होकर स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर 'मुख्य अतिथि' बना है। यह न केवल आपसी सम्मान का परिचायक है, बल्कि यह भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति की सफलता का भी प्रमाण है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की यह राजकीय यात्रा किसी शासनाध्यक्ष की पहली राजकीय यात्रा भी है, जिसकी मेजबानी राष्ट्रपति मुइज्जू नवंबर 2023 में पदभार ग्रहण करने के बाद से कर रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि मालदीव में एक परम्परा रही है कि नया राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति पहला दौरा भारत का करता है लेकिन मुइज्जू ने सबसे पहला दौरा तुर्की का किया था उसके बाद वह संयुक्त अरब अमीरात गये थे। उसके बाद उन्होंने चीन की बहुप्रचारित यात्रा भी की थी लेकिन उन्हें जब दूसरों के कर्ज जाल और भारत की निस्वार्थ मदद के बीच का अंतर समझ आया तो पिछले साल उन्होंने दो बार भारत का दौरा किया था और अब उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया तो वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।

इस तरह देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा एक प्रतीकात्मक ही नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों में आई खटास के बाद एक 'रीसेट' का संकेत देती है, बल्कि यह दिखाती है कि भारत किस तरह अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को दीर्घकालिक दृष्टि से संभालता है।

बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल 60 वर्षों के द्विपक्षीय संबंधों का उत्सव है, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा भी तय करती है। भारत और मालदीव के संबंध अब केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक साझेदारी नहीं हैं— वे समुद्री सुरक्षा, विकास, और क्षेत्रीय संतुलन के मजबूत स्तंभ बनते जा रहे हैं। यह यात्रा एक स्पष्ट संकेत देती है कि भारत, आलोचना से विचलित हुए बिना, अपने पड़ोस में स्थिरता और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। और यही किसी भी परिपक्व वैश्विक शक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

बड़ी जीत है द रेजिस्टेंट फ्रंट का आतंकी संगठन घोषित होना

ऑपरेशन सिंदूर में पाक को करारी मात देने के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में वातावरण बनाने के लिये तत्पर हुआ। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती देने के लिये ही भारत ने अमरीका समेत 32 देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे थे।

पहलगाम में जब आतंकी हमले में निर्दोषों का रक्त बहा, आहें एवं चीखें गूंजी, जिसने न केवल देश एवं दुनिया को झकझोर दिया था, बल्कि यह संकेत भी दे दिया कि आतंकवाद की जड़ें अब भी जीवित हैं और उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और सीमा-पार समर्थन प्राप्त है। लेकिन इस बार एक बड़ा परिवर्तनकारी एवं प्रासंगिक कदम अमेरिका की ओर से सामने आया है, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की मुखौटा इकाई द रेजिस्टेंट फ्रंट (टीआरएफ) को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया, इस तरह टीआरएफ की पहचान और आतंक के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता का नया अध्याय लिखा गया है। यह कदम केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि आतंक के विरुद्ध वैश्विक मंच पर एक रणनीतिक संदेश है कि अब छद्म युद्ध और पनपते आतंक के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही का युग आ गया है। अमेरिका का यह कदम भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास इस बात के द्योतक है कि आतंकवाद से निपटने के मोर्चे पर भारत सफल हो रहा है। अमेरिका के इस फैसले ने न सिर्फ टीआरएफ के आतंकी चेहरे से बेपर्दा किया है, बल्कि पाकिस्तान की उन नापाक हरकतों को भी बेनकाब कर दिया, जिन्हें वह खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताकर छिपाता आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे भारत-अमेरिका के बीच मजबूत आतंकवाद-रोधी सहयोग का प्रमाण बताया है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग की जरूरत पर बल दिया है।

टीआरएफ दिखने में एक स्थानीय कश्मीरी संगठन होने का भ्रम देता है, लेकिन असल में यह लश्कर-ए-तैयबा और उसके सरगना हाफिज सईद की पुरानी साजिश का नया चेहरा है। पाकिस्तान-समर्थित आतंकी संगठनों को नया नाम एवं नये रूप में प्रस्तुत करना पाक की एक साजिश एवं सोची-समझी रणनीति है, ताकि दुनिया के सामने वह अपने दामन को पाक-साफ दिखा सके। एक और विडम्बनापूर्ण स्थिति यह है कि पाक ने इसे इस तरह पेश किया जैसे यह कश्मीर का स्थानीय संगठन हो। यह जगजाहिर है कि कई बड़े आतंकी संगठन पाकिस्तान की धरती से संचालित किए जा रहे हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिद्दीन प्रमुख हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कई बार ये सवाल उठे और पाक को आतंक पोषित स्वीकार्य किया जाने लगा। उसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने रणनीति बदली और आतंकी संगठनों के नाम भी बदलने शुरू कर दिए। टीआरएफ इसका एक उदाहरण है। इसका गठन 2019 के अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद हुआ और इसका उद्देश्य भारत में आतंकी घटनाओं को 'स्वदेशी विद्रोह' की आड़ में अंजाम देना है। पहलगाम हमला भारत के उस प्रयास को चुनौती देता है जो वह 'पर्यटन और विकास के माध्यम से कश्मीर को मुख्यधारा में लाने' के लिए कर रहा है। जब भी कश्मीर में शांति की बहार आती है, ऐसे आतंकी संगठन हिंसा का तूफ़ान लेकर आते हैं। टीआरएफ ने सोशल मीडिया, इंटरनेट और कूटनीतिक शब्दजाल का इस्तेमाल करके अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को 'कश्मीरी प्रतिरोध आंदोलन' के रूप में पेश करने की कोशिश की, जबकि उसके तार रावलपिंडी और आईएसआई के आतंकवाद समर्थन तंत्र से सीधे जुड़े हैं। मगर, अमेरिका की ओर से इसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाना इस बात का सबूत है कि आतंकियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के इरादों को किसी छद्म नाम की आड़ में छिपाया नहीं जा सकता।

अमेरिका द्वारा टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाना भारत की एक बड़ी राजनयिक एवं कूटनीतिक सफलता है। यह दिखाता है कि भारत की तीक्ष्ण एवं ताकतवर विदेश नीति अब केवल घटनाओं की निंदा तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण की रणनीति पर आधारित है। जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्तावों को भी बल देती है। भारत पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध वर्षों से चेतावनी देते हुए दुनिया को आतंकमुक्त बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक स्तर पर विभिन्न देशों को आतंक के खिलाफ एकजुट करने के प्रयास तेज किये हैं। ऐसे में अमेरिका पर भी यह साबित करने का दबाव बना है कि वह आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड न अपनाये। क्योंकि अमेरिका का दोगलापन चर्चा में रहा है, एक तरफ अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का दावा करता है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और विश्व बैंक से बड़ी धनराशि कर्ज के रूप में दी जाती है। एक तरफ राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़े होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आतंकवाद की नर्सरी चलाने वाले पाकिस्तान को लेकर अपने नरम रुख का इजहार भी करते रहते हैं। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का ढुलमुल रवैया भी हैरान करने वाला है। सवाल यह है कि जब अमेरिका यह मानता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पाल-पोस रहा है, तो वह वैश्विक संस्थाओं से उसे वित्तीय मदद रोकने की वकालत क्यों नहीं करता है?

ऑपरेशन सिंदूर में पाक को करारी मात देने के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में वातावरण बनाने के लिये तत्पर हुआ। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती देने के लिये ही भारत ने अमरीका समेत ३२ देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे थे। इन देशों को पुख्ता सबूतों के साथ बताया गया कि टीआरएफ पाकिस्तान प्रायोजित लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है। संभवत: भारत के यही प्रयास इस संगठन के खिलाफ अमरीका के सख्त फैसले का आधार बनी। अमरीका ने इससे पहले २००१ में भारतीय संसद पर हमले के बाद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को आतंकी संगठन घोषित किया था। पाकिस्तान इन दोनों संगठनों की तरह टीआरएफ को भी भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। निश्चित ही अमेरिका की यह ताजा कार्रवाई स्वागतयोग्य है, लेकिन भारत को अब केवल प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कमर कसते हुए प्रक्रिया दिखानी चाहिए। उसे सीमा पार सर्जिकल/ड्रोन स्ट्राइक की नीति को और मजबूत करना चाहिए। आतंकी समर्थकों की फंडिंग रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों की मांग करनी चाहिए। घरेलू स्तर पर खुफिया तंत्र और साइबर निगरानी को और सक्रिय एवं आधुनिक बनाना चाहिए। वैश्विक मंचों पर एफएटीएफ, यूएन, और जी २० जैसे संगठनों में पाकिस्तान की आतंक-समर्थक भूमिका को बार-बार उजागर करना चाहिए। आज आवश्यकता है कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक और शांति-प्रिय राष्ट्र एक मंच पर एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टोलरेंस पॉलिसी अपनाएं। किसी भी राष्ट्र को- चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, आतंकियों की शरणस्थली बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करना पहला कदम है, अब इसकी जड़ों को नष्ट करना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। पाकिस्तान सरकार, सेना और आतंक के नापाक गठजोड़ पर जब तक सभी देश एकमत नहीं होंगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचेगी। सवाल यह भी है कि जब पाकिस्तान आतंकी संगठनों का खुलेआम समर्थन करता रहता है तो उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट में डालने से परहेज क्यों किया जा रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि अमरीका के ताजा कदम के बाद एफएटीएफ और दूसरी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां टीआरएफ की फंडिंग की जांच करेंगी।

पहलगाम का हमला एक बार फिर हमें चेतावनी देता है कि आतंकवाद केवल सुरक्षा का संकट नहीं, बल्कि सभ्यता, शांति और मानवता का अपमान है। हमें अब शब्दों से आगे बढ़कर संकल्प और कार्यवाही की ओर बढ़ना होगा। भारत को अब केवल प्रतिकार नहीं, बल्कि निर्णायक प्रहार की नीति अपनानी चाहिए ताकि अगली पीढ़ी एक ऐसे भारत में सांस ले सके जहां 'कश्मीर' केवल खूबसूरती का पर्याय हो, आतंक का नहीं। भारत को वैश्विक मंचों पर टीआरएफ को बेनकाब करने की मुहिम जारी रखनी चाहिए, ताकि इस संगठन को फिर फन उठाने का मौका न मिले।

- ललित गर्ग

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता: एक क्रांतिकारी कदम

ललित गर्ग

मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में जिस प्रकार से गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता पर जोर दिया, उसी का परिणाम है यह करार। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि अब भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है, जो अपने हितों की रक्षा करते हुए विश्व से संवाद करता है।

भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की अंतिम स्वीकृति ने न केवल वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य को भी एक नई दिशा दी है। दोनों देशों के बीच आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का फायदा दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से संरक्षणवाद बढ़ा है, उसमें ऐसे व्यापार समझौतों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। इस समझौते से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल अमेरिका बल्कि अन्य देशों को भी भारत की मजबूत होती स्थिति का आइना दिखाया है, जो उनकी दूरगामी एवं कूटनीतिज्ञ राजनीति का द्योतक है। इस समझौते को मौजूदा दौर में दुनियाभर में जारी बहुस्तरीय तनाव, दबाव एवं दादागिरी की राजनीति के बीच एक बेहतर एवं सूझबूझभरी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। यह छिपा नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने शुल्क के मोर्चे पर एक बड़ा द्वंद्व एवं संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन भारत ने इस द्वंद्व के बीच झूकने की बजाय नये रास्ते खोजे हैं। निश्चित ही यह व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) महज एक कागज़ी करार नहीं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के स्वप्न को मूर्त रूप देने की ठोस रणनीति है। जहां एक ओर यह समझौता 99 प्रतिशत टैरिफ को समाप्त कर वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, कृषि व रत्न-आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को नई उड़ान देगा, वहीं दूसरी ओर छोटे उद्यमों, मछुआरों और किसानों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाएगा। भारत के ग्रामीण अंचलों से हल्दी, दाल, अचार जैसे उत्पाद अब ब्रिटिश बाजारों में अपनी महक फैलाएंगे।

मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में जिस प्रकार से गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता पर जोर दिया, उसी का परिणाम है यह करार। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि अब भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है, जो अपने हितों की रक्षा करते हुए विश्व से संवाद करता है। यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह सेवा क्षेत्र, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, निवेश, सामाजिक सुरक्षा, और दोहरे कराधान जैसे क्षेत्रों में भी भारतीयों के लिए नए दरवाज़े खोलता है। खासकर ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए यह राहत का संदेश है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिल सकेगी। यह समझौता इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि अब तक अमेरिका की ओर से पैदा किये गये किसी दबाव के आगे भारत ने झुकना स्वीकार नहीं किया और उसने भारत-ब्रिटेन जैसे नये विकल्पों को खड़ा करने और पुराने को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाये हैं।

ब्रिटेन के साथ यह एफटीए एक उदाहरण है कि कैसे भारत न्यायसंगत और समावेशी व्यापार समझौते कर सकता है, जिसमें न तो अपने किसानों, न ही डेयरी क्षेत्र या छोटे उत्पादकों को नुकसान होता है। भारत ने संवेदनशील क्षेत्रों को समझौते से बाहर रखकर आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा की अपनी नीति को बरकरार रखा है। वर्तमान में भारत का वैश्विक व्यापार लगभग 21 अरब डॉलर है, जो इस समझौते के बाद 2030 तक 120 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना रखता है। यह न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग हिस्सेदारी को 17 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने में सहायक होगा। इस करार के साथ, मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि जब नियोजित दृष्टिकोण, वैश्विक प्रतिष्ठा और साहसिक निर्णय साथ चलते हैं, तो भारत जैसे विकासशील देश भी वैश्विक मंच पर निर्णायक बन सकते हैं।

भारत और ब्रिटेन के बीच सीईटीए के अस्तित्व में आने से एक नये आर्थिक सूर्य का उदय हुआ है, जिससे रोजगार सहित अनेक उन्नत राष्ट्र-निर्माण के अवसर सृजित होंगे। सीईटीए की संकल्पना आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के अनुरूप ही है। यह मोदी सरकार की भारत को 2047 तक विकसित बनाने की संकल्पना से जुड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने भारत को तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनाने के अपने संकल्प में नये पंखों को जोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास को फिर से स्थापित करने तथा इसे भारतीय और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए एक दृढ़ रणनीति अपनाई है। विकसित देशों के साथ एफटीए इस रणनीति के केंद्र में है। ऐसे समझौते व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं। पिछली यूपीए सरकार ने भारत के व्यापारिक दरवाजे प्रतिद्वंद्वी देशों के लिए खोलकर भारतीय व्यवसायों को खतरे में डालने वाला रवैया अपनाया था, लेकिन अतीत की उन बड़ी भूलों को सुधारा जा रहा है, जो नये भारत-विकसित भारत का आधार है।

मोदी के मेड इन इंडिया संकल्प की दृष्टि से यह डील बेहद अहम है। इससे करीब 99 प्रतिशत निर्यात यानी यहां से ब्रिटेन जाने वाली चीजों पर टैरिफ से राहत मिलेगी। इसी तरह ब्रिटेन से आनी वाली चीजें भारत में सस्ती मिल सकेंगी। जिससे आम लोगों को अधिक गुणवत्ता वाला सामान सस्ते में सुलभ होगा और जीवनस्तर में व्यापक सुधार होगा। डील से एक बड़ा फायदा होगा टेक्सटाइल्स, लेदर और इलेक्ट्रॉनिक्स को। इनसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। अभी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.8 प्रतिशत है, जबकि चीन की 28.8 प्रतिशत। इसी तरह, देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 17 प्रतिशत है और सरकार इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती है। इस तरह की डील से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तर पर प्रदर्शन में सुधार होगा। कृषि सेक्टर को भी उन्नत बनाने एवं अधिक उत्पाद की दृष्टि से व्यापक फायदा होगा। इसके लिए इस समय भारत की बातचीत अमेरिका से भी चल रही है। लेकिन वहां कृषि और डेयरी प्रॉडक्ट्स को लेकर रस्साकशी है। अमेरिका इन दोनों क्षेत्रों में खुली छूट चाहता है, जबकि अपने लोगों के हितों को देखते हुए भारत ऐसा नहीं कर सकता। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार होने से भारत के कृषि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

क्रांतिकारी सुधारों, नवाचार, तकनीक, कारोबारी सुगमता और प्रधानमंत्री के वैश्विक व्यक्तित्व ने भारत को एक आर्थिक सूरज के रूप में उभारने में मदद की है, जहां विपुल संभावनाएं हैं। आज दुनिया भारत की ओर आशाभरी नजरों से देख रही है और भारत की अद्भुत विकासगाथा का हिस्सा बनना चाहती है। प्रमुख देशों द्वारा एक के बाद एक एफटीए इसी मान्यता की पुष्टि करते हैं। ब्रिटेन के साथ यह व्यापार समझौता बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के एफटीए वस्तुओं और सेवाओं से कहीं आगे तक सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं नागरिक हितों तक जाते हैं। आस्ट्रेलियाई एफटीए के साथ भारत ने दोहरे कराधान का मुद्दा सुलझाया, जो आईटी कंपनियों की परेशानी बढ़ा रहा था। ब्रिटेन के साथ समझौते का एक अहम बिंदु दोहरे अंशदान से जुड़ा है। यह ब्रिटेन में नियोक्ताओं, अस्थायी भारतीय कर्मियों को तीन वर्षों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देता है। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को अब अनेक सुविधाएं मिलेगी।

साल 2014 के बाद से भारत ने मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ईएफटीए के साथ फ्री व्यापारिक समझौते किये हैं। ईएफटीए का अर्थ है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। यह एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसमें चार यूरोपीय देश शामिल हैं- आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। यूरोप से बातचीत जारी है, जिसे जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। अर्थ-व्यवस्था के मोर्चे पर आने वाली चुनौतियों से निपटने में ऐसे समझौते सहायक होंगे। इस बीच, अगर भारत की अमेरिका के साथ अच्छी व्यापार डील होती है तो उससे भी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की ओर कदम बढ़ेंगे। लेकिन ब्रिटेन से समझौता केवल व्यापार नहीं, भविष्य का निर्माण है। यह कृषि को समृद्धि, उद्योग को विस्तार, युवाओं को अवसर, और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर सशक्त करता है। निश्चित ही जहां बाजार बनते हैं अवसरों के, वहीं नीति बनती है भविष्य की नींव। भारत और ब्रिटेन के इस करार से विश्व सुनेगा अब भारत की गूंज!

लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

विपक्ष की लोकतंत्र पर चिंता या सत्तालोभ की राजनीति?

विपक्षी दल मोदी एवं भाजपा पर लगातार आक्रामक हैं। राहुल गांधी और अन्य दलों के नेता संविधान की प्रति लहराकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे संविधान खतरे में है और उन्हें उसे बचाना है। लेकिन भारत की जनता अब परिपक्व एवं समझदार हो गयी है, उसे अच्छा-बुरे में फर्क दिखता है।

भारतीय लोकतंत्र आज विश्व के सबसे बड़े, जीवंत और जागरूक लोकतंत्रों में गिना जाता है। यह संविधान की मजबूत नींव, संस्थाओं की पारदर्शिता और जनता की जागरूकता से संचालित होता है। परंतु विडंबना यह है कि देश का विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी, बार-बार लोकतंत्र और संविधान पर खतरे की झूठी दुहाई देकर एक अनावश्यक और निरर्थक बहस छेड़ते रहे हैं, वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा को घेरने एवं दोषी ठहराने के लिये न केवल उन पर आधारहीन आरोप लगाते रहते हैं, वरन देश की संवैधानिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और संविधान के ही खतरे में होने का राग अलापते हुए उन्हें लांछित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे नेता संविधान की दुहाई देते हैं, वे स्वयं संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। लोकतंत्र की आत्मा पर इस तरह का प्रहार विपक्ष की भूमिका पर एक बड़ा प्रश्न है। विडम्बना एवं चिन्ताजनक है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं में भी मोदी-भाजपा का विरोध करते-करते देश-विरोध पर उतर जाते हैं, जिससे विदेशों में भारत की छवि का भारी नुकसान होता है और विदेशियों को लगता था कि भारत में लोकतंत्र और संविधान ढह रहा है।

नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं उनके सहयोगी जब यह कहते हैं कि 'देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है', 'संविधान खतरे में है', तब यह केवल एक राजनीतिक शगूफा प्रतीत होता है, न कि कोई तर्कसम्मत आलोचना। यदि वास्तव में लोकतंत्र खतरे में होता, तो क्या वे हर मंच से खुलकर सरकार की आलोचना कर पाते? क्या संसद, मीडिया, चुनाव आयोग, और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं उनके वक्तव्यों को स्थान देतीं? असल में तो 1975 में लोकतंत्र एवं संविधान खतरे में आये थे जब तत्कालिन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने हेतु अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 'आंतरिक अशांति' के आधार पर आपातकाल लगाया तथा लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर हजारों नेताओं एवं बेगुनाह लोगों को कठोर कानूनों के अंतर्गत जेल भेज दिया। आजादी के बाद तब पहली और आखरी बार लोकतंत्र खतरे में आया था, तब संविधान भी खतरे में चला गया था। राहुल गांधी अपने गिरेबान में झांकने एवं कांग्रेस के अतीत को देखने की बजाय मोदी-भाजपा पर लोकतंत्र एवं संविधान को खतरे में डालने का बेबुनियाद, भ्रामक एवं आधारहीन आरोप मंढते हैं। इन त्रासद स्थितियों में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा नहीं, बल्कि अपने खोए हुए जनाधार को पुनः प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। विशेषतः लोकसभा हो या विधानसभा के चुनाव-इनमें जरूरी एवं जनता से जुड़े विषयों को उठाने की बजाय लोकतंत्र एवं संविधान के खतरे में होने के राग से जनता को गुमराह करना आम बात हो गयी है।

देशभर में एवं अनेक राज्यों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार आदि के अवैध घुसपैठियें बड़ी मात्रा में घुस आये हैं। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिये इन घुसपैठियों को इन विपक्षी दलों की शह पर ही जगह मिल रही है, ये घुसपैठियें न केवल फर्जी तरीकों से आधार, पैन, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेज प्राप्त कर कई निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता-सूचियों में अपना नाम अंकित करा लिया है। यह लोकतंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनसंख्या संतुलन के लिए गंभीर खतरा है, चुनाव आयोग ने इस पर अपना रुख सख्त करते हुए सभी राज्यों में 'मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण' का निर्णय लिया है। बिहार में वह ऐसे लोगों की पहचान संबंधी पहल कर चुका है, पर विपक्ष को इस पर आपत्ति है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी। न्यायालय ने आयोग की इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई।

विपक्ष लम्बे समय से चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है, कभी निष्पक्ष मतदान पर तो कभी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर सवाल उठाते रहा है। चूंकि चुनाव ही सत्ता की सीढ़ी है, इसलिए लोकसभा चुनाव में परास्त होने और अनेक राज्यों में अप्रासंगिक होने से चुनाव आयोग पर आरोप तथा लांछन लगाना विपक्ष के लिए काफी आसान हो गया है। कभी वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों और निर्णयों पर अंगुली उठाता है, कभी उसे भाजपा के इशारे पर काम करने वाला बताता है, कभी ईवीएम, मतदाता सूची में अनियमितता, डाटा देने में विलंब, दलीय पक्षपात आदि का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग की छवि नष्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को हरी झंडी देकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी।

विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना और वैकल्पिक नीतियों के माध्यम से शासन को दिशा देना होती है। किंतु आज का विपक्ष न तो पाकिस्तान-चीन के खतरनाक मनसूबों, न गरीबी, न महंगाई, न बेरोजगारी, न सांप्रदायिक सौहार्द, न सीमा पर पड़ोसी देशों की चुनौती, और न ही किसानों, युवाओं और महिलाओं की समस्याओं को लेकर कोई ठोस योजना प्रस्तुत कर पा रहा है और न ही इन बुनियादी मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा पा रहा है।

कारगिल: वीरता जहाँ लहू बनकर बही, जयघोष बनकर गूंजी

[तू क्या देगा भारत को? – कारगिल की गूंजता प्रश्न]
[कारगिल : जहाँ साँस लेना भी युद्ध था, फिर भी तिरंगा फहराया]

जब भारत की मिट्टी शहीदों के लहू से रंग जाती है, तो वह न केवल इतिहास रचती है, बल्कि अमरता का वह गीत गाती है जो हर भारतीय के रग-रग में देशभक्ति की आग जला देता है। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर बहा हर खून का कतरा आज भी पुकारता है – "मैंने अपने प्राण मातृभूमि को सौंप दिए, अब तू क्या देगा भारत को?" 26 जुलाई कोई साधारण दिन नहीं, यह भारत के शौर्य का वह स्वर्णिम पन्ना है जो हर हृदय में गर्व की लौ जलाता है। यह वह दिन है जब भारत ने दुनिया को बता दिया कि उसकी सीमाओं की ओर आँख उठाने वालों का दुस्साहस कुचल दिया जाता है, और मातृभूमि की रक्षा के लिए उसके वीर सपूत मौत को भी गले लगाने से नहीं डरते। कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य जीत की गाथा नहीं, बल्कि यह उस अटूट संकल्प की कहानी है, जिसने भारत को अभेद्य बनाया।

मई 1999 में शुरू हुआ कारगिल युद्ध भारतीय सेना के लिए एक ऐसी अग्निपरीक्षा था, जहाँ दुश्मन की गोलियाँ ही नहीं, बल्कि प्रकृति की क्रूरता भी हर कदम पर चुनौती दे रही थी। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर कारगिल, द्रास और बटालिक की चोटियों पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया था। 16,000 से 18,000 फीट की ऊँचाई पर, जहाँ साँस लेना भी एक युद्ध था, दुश्मन ने अपनी स्थिति मज़बूत कर ली थी। हाड़ जमा देने वाली ठंड, खतरनाक भूभाग और छिपे हुए दुश्मन – यह सब मिलकर मौत का नंगा नाच रच रहे थे। लेकिन भारतीय सेना ने इस चुनौती को न केवल स्वीकारा, बल्कि अपने अदम्य साहस से उसे परास्त कर दिखाया। "ऑपरेशन विजय" की शुरुआत हुई, जो केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बन गया।

इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया। टाइगर हिल, तोलोलिंग और पॉइंट 5140 जैसी चोटियाँ, जिन्हें दुश्मन ने अभेद्य किला समझा था, भारतीय जवानों की वीरता के सामने धूल में मिल गईं। इस युद्ध में 527 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, और लगभग 1,363 घायल हुए। फिर भी, कोई पीछे नहीं हटा। उनकी बंदूकें केवल बारूद नहीं, बल्कि देशभक्ति का जज़्बा उगल रही थीं। हर तिरंगा जो इन चोटियों पर लहराया, वह केवल कपड़ा नहीं, बल्कि हर शहीद की अंतिम साँस और भारत के गौरव का प्रतीक था। इन चोटियों पर लहराता तिरंगा उस माँ की मुस्कान था, जिसने अपने बेटे को देश के लिए खोया, और उस पिता का गर्व था, जिसने अपने लाल की शहादत को सलाम किया।

कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें 'शेरशाह' का खिताब मिला, ने पॉइंट 5140 पर विजय पाकर "ये दिल मांगे मोर" का नारा बुलंद किया। यह नारा केवल एक उद्घोष नहीं था, बल्कि हर भारतीय के सीने में धड़कते जज़्बे की गूंज था। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ने अपनी वीरता से दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और कैप्टन अनुज नैय्यर जैसे वीरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आन-बान-शान की रक्षा की। इनमें से कई सैनिकों की उम्र 20-25 वर्ष थी, फिर भी उनकी वीरता ने पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित ये वीर केवल नाम नहीं, बल्कि देशभक्ति की वह ज्योति हैं जो कभी बुझने वाली नहीं।

कारगिल युद्ध केवल सैनिकों की वीरता की कहानी नहीं था, बल्कि यह पूरे भारत की एकजुटता का जीवंत प्रमाण था। देश के कोने-कोने से लोग अपने जवानों के लिए प्रार्थनाएँ, पत्र और स्नेह भेज रहे थे। स्कूलों में बच्चे मोमबत्तियाँ जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, महिलाएँ अपने आँचल में दुआएँ बाँध रही थीं, और बुजुर्ग अपने आश्रय छोड़कर सैनिकों के समर्थन में सामने आए। मीडिया ने 24x7 कवरेज के साथ इस युद्ध को हर भारतीय के घर तक पहुँचाया, और पहली बार देश ने एकजुट होकर युद्ध को अपने दिल से महसूस किया। यह वह समय था जब हर भारतीय ने खुद को इस युद्ध का हिस्सा समझा, और यह संगठित देशप्रेम एक ऐसी मिसाल बना जो आज भी हमें प्रेरित करता है।

इस युद्ध ने भारत को कई सबक सिखाए। कारगिल के बाद भारत ने अपनी रक्षा नीति, सैन्य तैयारियों और खुफिया तंत्र को और मज़बूत किया। रक्षा मंत्रालय ने निगरानी तंत्र को उन्नत किया, और सशस्त्र बलों ने अपनी रणनीतियों में सुधार किया। यह युद्ध एक चेतावनी था कि देश की सुरक्षा केवल सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि विचारों, नीतियों और एकता में भी सुनिश्चित करनी होगी। कारगिल ने हमें सिखाया कि शांति की चाहत हमें कमजोर नहीं बना सकती; हमें हमेशा सजग और तैयार रहना होगा।

हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, लेकिन यह दिन केवल औपचारिकता का नहीं है। यह वह दिन है जब हमें खुद से पूछना चाहिए – क्या हम उस भारत के योग्य हैं, जिसके लिए किसी माँ ने अपने बेटे को खोया? यह दिन हमें याद दिलाता है कि शहीदों का बलिदान केवल स्मृतियों में नहीं रहना चाहिए; उसे हमारे कर्मों, संकल्पों और राष्ट्रनिर्माण में उतारना होगा। कारगिल के शहीदों ने हमें एक ऐसा भारत सौंपा, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस भारत को और मज़बूत, समृद्ध और एकजुट बनाएँ।

कारगिल विजय दिवस हमें यह भी सिखाता है कि सीमाएँ केवल नक्शों में नहीं होतीं, बल्कि हर दिल में भी एक सीमा होती है – सत्य और असत्य के बीच, देशप्रेम और स्वार्थ के बीच। जो इस सीमा की रक्षा करता है, वही सच्चा देशभक्त है। आज जब हम आजादी के अमृत काल की ओर बढ़ रहे हैं, कारगिल के शहीदों की वह पुकार हमें याद रखनी होगी – "देश सोता नहीं, देश सजग होता है।" यह पुकार हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को केवल अपने लिए न जिएं, बल्कि उस मिट्टी के लिए जिएं, जिसे हमारे वीरों ने अपने लहू से सींचा है।

कारगिल की चोटियों पर गूंजे जयकारों ने हमें जो आत्मबल दिया, उसे केवल स्मृति बनाकर नहीं रखना है। उसे कर्म में, संकल्प में, और राष्ट्रनिर्माण की नींव में बदलना है। यह वही भारत है, जिसके लिए शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनका लहू इस मिट्टी में घुल गया है, और अब हमें उसे अपने जीवन की दिशा बनानी है। जब तिरंगा गर्व से लहराता है, तो उसमें कारगिल की ठंडी हवाओं की साँसें भी समाई हैं, जो हर शहीद की अंतिम साँस की साक्षी हैं। इस कारगिल विजय दिवस पर उन वीरों को नमन करें, और यह संकल्प लें कि जब देश पुकारे, तो हमारा उत्तर होगा – मैं हूँ तैयार! कारगिल की यह गाथा हमें सिखाती है कि भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक भावना है, एक संकल्प है, और एक ऐसा गीत है जो हर भारतीय के दिल में गूंजता है। कारगिल विजय दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा देश तभी अजेय रहेगा, जब हम एकजुट रहेंगे, सजग रहेंगे, और अपने शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए समर्पित रहेंगे। यह वह दिन है जब हमें अपने वीरों के बलिदान को न केवल याद करना है, बल्कि उसे अपने जीवन का मंत्र बनाना है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत",

मेवात में 'खाता फ्रीज' बना नासूर

साइबर क्राइम के कारण आए दिन सुर्खियों में रहने वाले मेवात में बहुतेरे दुकानदार अपने बैंक खातों के फ्रीज होने की समस्या से जूझ रहे हैं। राजस्थान के मेवात में साइबर ठगी की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए भरतपुर पुलिस ने **'ऑपरेशन एंटी-वायरस'** शुरू किया जिसके सार्थक परिणाम भी सबके सामने आए लेकिन दुकानदार आज भी बैंक खाता फ्रीज होने जैसी समस्या से छुटकारा मिलने की राह ताक रहे हैं। बैंक अधिकारियों का तर्क है कि दुकानदार के खाते में फ्रॉड की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर होने पर पुलिस उनके खातों को फ्रीज करने का निर्देश देती है जिसकी पालना करना हमारी मजबूरी है। वहीं पुलिस अफसरों का तर्क यह होता है कि यह अनुसंधान का मामला है, इसलिए खाते फ्रीज कराना ज़रूरी है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है, जिससे यह तय हो सके कि ग्राहक उन्हें जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है कि वह राशि फ्रॉड की है या सुरक्षित है। उन्हें तो पता तब चलता है कि जब उनका बैंक खाते से लेनदेन ही बंद हो जाता है। बैंक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पुलिस ने उनके खाते का फ्रीज करा दिया है।

हालात यह है कि किसी दुकानदार का गुजरात की क्राइम ब्रांच ने तो किसी अन्य दुकानदार का तमिलनाडु की क्राइम ब्रांच ने खाता फ्रीज कराया है। पुलिस थानों में चक्कर काटते हैं तो भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता है। दुकानदारों का कहना है कि इससे उन्हें व्यापार करने में काफी परेशानी आ रही है। मेवात में बैंक खाता फ्रीज होने जैसी समस्या से जूझते कई दुकानदारों ने तो ऑनलाइन पेमेंट लेना ही बंद कर दिया है। दुकानदारों के इस तरह के कदम से उन ग्राहकों को असुविधा झेलनी पड़ रही है जो सही तरीके से ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं और उनकी जेब में नकदी नहीं होती है। राजस्थान के मेवात में ऐसे सैकड़ों की संख्या में बैंक खाते हैं जो अब भी फ्रीज पड़े हैं और दुकानदार बैंक और पुलिस के चक्कर काटते-काटते थक चुके हैं। वर्ष 2024 में **'ऑपरेशन एंटी-वायरस'** तत्कालीन आईजी राहुल प्रकाश को इसलिए शुरू करना पड़ा कि डीग देश में साइबर अपराध का नम्बर वन हॉट स्पॉट बन गया था। यहां के साइबर अपराधियों से देश के हर प्रदेश के लोग त्रस्त थे। कुछ मामलों में तो पीड़ितों ने आत्महत्या तक कर ली थी। ऐसे कारणों से साइबर अपराध पर अंकुश लगाना सरकार के प्राथमिकताओं में शामिल हुआ। स्थिति ऐसी हो गई कि देश के कुल साइबर अपराधों में से 21 फीसदी केवल डीग से हो रहे थे। **'ऑपरेशन एंटी-वायरस'** के तहत पुलिस ने मेवात में गांव-गांव जाकर धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ पंचायत कर समझाया। इतना ही नहीं, गांव के युवाओं को यह समझाया कि साइबर क्राइम का रास्ता आपका भविष्य खराब कर देगा। पुलिस ने स्कूल, कॉलेजों में साइबर कानून और सुरक्षा को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक करने का प्रयास किया। राजस्थान के मेवात में साइबर ठगी जैसे गोरखधंधे में युवा ही नहीं बल्कि बच्चे भी लिप्त पाए गए, जिन्हें उनके ठिकानों से पुलिस ने दबोचा। मेवात में कई बार पुलिस को विरोध भी झेलना पड़ा लेकिन पुलिस ने अपनी रणनीति से साइबर ठगों के मंसूबों पर पानी फेरा। मेवात में साइबर अपराध के खिलाफ माहौल बनने लगा तो जिम्मेदार ग्रामीण भी पुलिस की मदद करने को आगे आने लगे। इन मददगार ग्रामीणों ने सैकड़ों मोबाइलों को तोड़ने के साथ ही आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने **'ऑपरेशन एंटी-वायरस'** के तहत करीब सवा छह सौ मामले दर्ज कर 1 हजार से ज्यादा साइबर अपराधियों को पकड़ा जिनसे नकदी बरामद करने के साथ ही फर्जी सिम कार्ड, चोरी के मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और 300 से ज्यादा वाहन जब्त किए। पुलिस की रणनीति और कार्यकुशलता का ही परिणाम रहा कि रेंज में साइबर अपराधों में 83 प्रतिशत तक की कमी आई। मेवात में साइबर अपराध पर काफी हद तक अंकुश लगा पाने में पुलिस कामयाब रही है लेकिन अब भी यह अपराध पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है।

राजेश खण्डेलवाल

झारखंड में अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा नाम पर हुआ नामित

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची ,झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम नामित किया है । गुरुवार को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को मंजूरी देने सहित कुल 21 निर्णय लिए गए ।झारखंड सरकार ने गुरुवार को भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक कर दिय । यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अटल मोहल्ला क्लीनिक योजना का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ।पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने राज्य की शहरी मलिन बस्तियों में गुणवतापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए अगस्त 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी। राज्य में 140 अटल मोहल्ला क्लीनिक कार्यरत हैं, जो नि:शुल्क और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।

सोरेन मंत्रिमंडल द्वारा झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को मंजूरी देने सहित कुल 21 निर्णय लिए गए। झारखंड गठन के बाद सरायकेला के प्रथम उपायुक्त बंदना दादेल ने कहा कि वर्तमान में झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों

के लिए अलग-अलग अधिनियम हैं। मेडिकल और एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक व्यापक अधिनियम लाने का प्रस्ताव है। नियुक्तियों के लिए एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है।

देवघर में एक माह तक चलने वाली श्रावणी मेले के मद्देनजर मंत्रिमंडल द्वारा 10 जुलाई से 10 अगस्त तक 28 अस्थायी मेला चौकियों और 19 अस्थायी ट्रैफिक चौकियों की स्थापना को मंजूरी दी गई ।मंत्रिमंडल ने संयुक्त भर्ती नियम 2025 के गठन के बाद पूर्व में प्रकाशित पुलिस भर्ती विज्ञापनों को निरस्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भविष्य में होने वाली भर्तियों में पूर्व आवेदकों को शुल्क से छूट और सभी श्रेणियों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए 4339 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

झारखंड लोकसभा आयोग 2023 का परिणाम प्रकाशित, 342 उम्मीदवार सफल घोषित

आशिष अक्षत को प्रथम स्थान, अभय दुसरे ,रंजन तीसरे

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

रांची , झारखंड राजकीय सेवाओं के प्रतियोगी अभ्यार्थीयों द्वारा समय समय पर सड़क पर उतर कर आन्दोलन , सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के साथ झारखंड लोक सेवा आयोग के 2023 के लिए 342 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है। जहां जेपीएससी मेन्स एग्जाम में सफल हुए 864 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा 2023 के तहत 342 पदों पर भर्ती होनी थी जिसके लिए 342 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है। आपको बता दें कि जेपीएससी मेन्स एग्जाम में सफल हुए 864 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मेन्स एग्जाम व इंटरव्यू के प्राप्तांक के आधार पर अंतिम रूप से चयनितों की सूची जारी की गई है।

झारखंड सिविल सेवा परीक्षा 2023 परिणाम में आशीष अक्षत

प्रथम स्थान, अभय कज़रू दूसरे और रवि रंजन कुमार तीसरे, गौतम गौरव चौथे और श्वेता पांचवे स्थान पर है। छठे स्थान पर राहुल कुमार विश्वकर्मा, सातवें पर रोबिन कुमार, 8वें पर संदीप प्रकाश, 9वें पर स्वाति केशरी और 10वें पर राजीव रंजन है ।झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2023 के लिए आवेदन फरवरी 2024 में लिए थे। डिप्टी कलेक्टर के 207 और डीएसपी के 35 पद समेत कुल 342 वैकेंसी थी। भर्ती में उम्मीदवारों को उम्र में 7 साल की छूट दी गई थी। रिक्त पदों में 155 पद अनारक्षित थे। वहीं 88 पद एसटी, 31 एससी, 15 अन्य पिछड़ा वर्ग , 24 पिछड़ा वर्ग व 29 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित थे। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 22 अप्रैल 2024 को प्रकाशित हुआ था । जिसमें 7011 कैंडिडेट क्वालीफाई किये थे । मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 21 म ई को आया था पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) - 35,राज्य कर पदाधिकारी - 56,कारा अधीक्षक - 2झारखंड शिक्षा सेवा (कैटेगरी-2) - 10,जिला समादेष्टा - 1,सहायक निबंधक - 8,श्रमअधीक्षक-14,प्रोबेशन पदाधिकारी- 6,उत्पाद निरीक्षक - 3 मुख्य परीक्षा से लेकर इंटरव्यू और फिर फाइनल रिजल्ट तक प्रक्रिया में लगातार देरी और अस्पष्टता को लेकर आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे। अभ्यर्थियों ने मूल्यांकन में पारदर्शिता, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया, उत्तर कुंजी की शुद्धता और परिणामों की समयसीमा को लेकर काफी आक्रोश व्यक्त हुआ था ।

जब गुनहगार छूटते हैं और पीड़ित रह जाते हैं

2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों में लगभग 189 लोगों की जान गई। लगभग 19 वर्षों तक चले मुकदमे के बाद जब उच्चतम न्यायालय ने सबूतों के अभाव में 12 अभियुक्तों को बरी कर दिया, तो यह न्याय व्यवस्था, जांच एजेंसियों और अभियोजन की निष्क्रियता पर गहरी चोट थी। कमजोर जांच, फॉरेंसिक लापरवाही, जबरन कबूलनामे और गवाहों की सुरक्षा की अनदेखी ने पूरे मामले को खोखला बना दिया। यह घटना हमें बताती है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक, निष्पक्ष और जवाबदेह प्रणाली की आवश्यकता है। वरना जनता का भरोसा केवल व्यवस्था पर से ही नहीं, लोकतंत्र से भी उठ जाएगा।

प्रियंका सौरभ

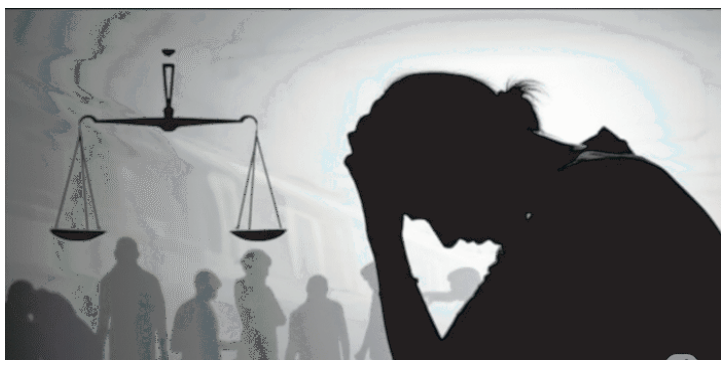

मुंबई में वर्ष 2006 में हुए लोकल ट्रेन धमाके देश के इतिहास की सबसे भयानक आतंकी घटनाओं में से एक थे। सात जगहों पर ट्रेनों में बम विस्फोट कर के 189 लोगों की जान ली गई और लगभग 800 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला केवल मानव शरीरों पर नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की आत्मा पर किया गया था। पूरा देश सन्न रह गया था। भय, आक्रोश और असहायता के बीच एकमात्र आशा थी – न्याय की। परंतु जब लगभग 19 वर्षों बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के 12 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, तब एक बार फिर यह प्रश्न गूंजने लगा कि क्या हमारे देश में पीड़ितों को कभी न्याय मिल भी पाता है?

यह निर्णय केवल एक अदालती प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस व्यवस्था की पोल खोलने वाला था जिसमें जांच एजेंसियों की निष्क्रियता, अभियोजन की लापरवाही और राजनीतिक हस्तक्षेप की मिलीजुली साजिश वर्षों से न्याय को घुटनों पर लाने का कार्य कर रही है। किसी भी न्यायालय का कार्य तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्रक्रिया के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देना होता है। लेकिन जब जांच ही लचर हो, जब सबूत इतने कमजोर हों कि अदालत उन्हें स्वीकार ही न करे, तो फिर न्यायालय भी विवश हो जाता है।

इस मामले में आरोपियों को सज़ा न मिल पाने का दोष न्यायालय पर मढ़ना आसान है, लेकिन वास्तव में जिम्मेदार वे अधिकारी हैं जिन्होंने इस गंभीर आतंकी हमले की जांच को हल्केपन और जल्दबाज़ी से अंजाम दिया। कई आरोपियों के कबूलनामे जबरन करवाए गए, जो कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में स्वीकार्य नहीं हैं। विस्फोट स्थलों से फॉरेंसिक साक्ष्य समय पर एकत्रित नहीं किए गए। गवाहों की सुरक्षा को नज़रअंदाज़ किया गया। चार्जशीट्स में विरोधाभासी बातें सामने आईं और अभियोजन पक्ष अदालत में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख सका।

इन सबका परिणाम यह हुआ कि वे लोग जो सालों से दोषियों को सज़ा दिलाने की उम्मीद में अदालतों के चक्कर काट रहे थे, उन्हें अंत में निराशा ही हाथ लगी। क्या इस देश में किसी आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या पीड़ित परिवारों की आंखों के आँसू, उनकी टूटती उम्मीदें और उनके जीवन की असुरक्षा हमारी व्यवस्था को झकझोरने के लिए काफी नहीं?

यह कोई पहला मामला नहीं है जहां न्याय व्यवस्था ने पीड़ितों को न्याय दिलाने में असफलता दिखाई हो। भोपाल गैस त्रासदी, हाशिमपुरा नरसंहार, 1984 सिख दंगे, और निठारी हत्याकांड – यह सभी उदाहरण हैं जहां या तो दोषी छूट गए या न्याय मिलने में इतनी देर हुई कि उसका कोई अर्थ ही नहीं बचा। यह सबूत हैं कि हमारी न्यायिक प्रणाली में समय, साक्ष्य और सत्य – तीनों की कमी होती जा रही है।

न्याय केवल अदालत में फैसले देने की प्रक्रिया नहीं है, वह समाज के उस विश्वास की रीढ़ है जो शासन और प्रशासन पर टिका होता है। यदि बार-बार अपराधी बच निकलें, यदि आतंकवादी छूट जाएं, और यदि पीड़ित सालों अदालतों की सीढ़ियां चढ़ते रहें तो वह विश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है।

मुंबई ट्रेन धमाके की जांच जिस प्रकार से की गई, वह बताता है कि हमारी जांच एजेंसियां न केवल तकनीकी रूप से कमजोर हैं, बल्कि वे राजनीतिक दबाव में काम करने के लिए अभिशप्त भी हैं। भारत में जांच का ढांचा ब्रिटिशकालीन मानसिकता पर आधारित है, जिसमें अपराधी को पकड़ने से ज़्यादा उसे रिहा करने पर ज़ोर होता है। और जब मामला आतंकवाद से जुड़ा हो, तो कई बार बेकसूरों को पकड़ कर जनता के गुस्से को शांत करने की कोशिश की जाती है। इससे असली अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं जाता, और सारा केस अदालत में दम तोड़ देता है।

इस मामले में भी कई ऐसे पहलू हैं जो चिंता पैदा करते हैं। जैसे – जांच में देरी, सबूतों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह न होना, अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य न होना, और गवाहों का मुकर जाना। इन सब कमियों के बावजूद यदि हम न्याय की उम्मीद करें, तो यह केवल छलावा होगा।

क्या न्यायपालिका को केवल मौन दर्शक बने रहना चाहिए? क्या उसका कोई दायित्व नहीं कि वह जांच की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए? जब अदालतों ने कई अन्य मामलों में विशेष जांच दल (SIT) गठित किए हैं, तो फिर इस गंभीर मामले में क्यों नहीं? न्यायिक सक्रियता केवल राजनैतिक मामलों या नागरिक अधिकारों तक ही सीमित क्यों?

वास्तव में न्याय प्रणाली को समयबद्ध, वैज्ञानिक और जवाबदेह बनाने के लिए एक सम्पूर्ण सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले तो अभियोजन विभाग को पुलिस से अलग कर स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अभियोजन किसी राजनीतिक दबाव या पुलिस की एकतरफा जांच का हिस्सा नहीं बनेगा।

दूसरे, गवाह सुरक्षा कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। आतंकवाद जैसे मामलों में गवाहों को धमकाना बहुत आम है, जिससे वे अदालत में बयान बदल देते हैं। तीसरे, जांच एजेंसियों को तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण दिए जाने चाहिए ताकि वे डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों को प्रभावी रूप से इकट्ठा कर सकें।

चौथे, फास्ट ट्रैक अदालतें बनाकर ऐसे मामलों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से करनी चाहिए, ताकि पीड़ितों को 19 साल तक न्याय की प्रतीक्षा न करनी पड़े। और पांचवां, यदि कोई जांच एजेंसी जानबूझकर कमजोर चार्जशीट बनाती है, तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है – मीडिया की भूमिका। मीडिया को भी आत्ममंथन करना होगा। जब कोई मामला अदालत में हो, तब मीडिया द्वारा किसी को दोषी या निर्दोष घोषित कर देना, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मीडिया ट्रायल से गवाहों पर दबाव बनता है और जनता का पूर्वग्रह उभरता है। यह भी कारण है कि न्याय अपने नैतिक स्वरूप से दूर होता जा रहा है।

आख़िर में यही कहा जा सकता है कि न्याय केवल कागज़ी प्रक्रिया नहीं है, वह एक जीवंत विश्वास है, जो प्रत्येक नागरिक के मन में इस सोच के साथ पलता है कि कोई उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता। जब यह विश्वास टूटता है, तब देश की आत्मा घायल होती है।

मुंबई ट्रेन धमाकों के पीड़ितों के साथ जो हुआ, वह केवल एक अदालती मामला नहीं है – वह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि यदि अब भी हमने अपनी व्यवस्था को नहीं सुधारा, तो अगली बार फिर कोई धमाका होगा, फिर निर्दोष मारे जाएंगे, फिर कोई माँ न्याय की भीख मांगेगी, और फिर कोई अदालत कहेगी – साक्ष्य नहीं मिले।

इस बार अगर हम नहीं जागे, तो इतिहास बार-बार यह प्रश्न पूछेगा – क्या भारत में न्याय केवल सुविधा भर है?

झारखंड में आज जोरदार बारिश, अगले पांच दिनों तक रहेगा प्रभाव

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

सरायकेला। झारखंड की राजधानी रांची और गढ़वा, बोकारो, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां में भारी बर्षा निम्न दबाव के कारण जारी है . सबसे ज्यादा 116 मिमी बारिश गढ़वा में दर्ज की गई. रांची में सड़कों पर पानी भरने से लग रहा था जैसे सड़कें नदियां बन गई हों. स्कूटी और कारें तैरती नजर आईं यहां . यहां बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है.

अगले 48 घंटे के दौरान यह सिस्टम उत्तर ओड़िशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्तीय इलाकों और झारखंड के दक्षिणी हिस्से होते हुए पश्चिमोत्तर की ओर बढ़ेगा। इससे राजधानी समेत सात जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला जिले में भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि, शेष जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी घटनाएं हो सकती हैं। रांची मौसम विज्ञान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण यह बारिश हो रही है. साथ ही, मॉनसून ट्रैफ झारखंड के जमशेदपुर, सरायकेला से गुजर रहा है, जिससे अगले पांच दिन तक बारिश जारी रहेगी. खासकर दोपहर 2 बजे के बाद मौसम बदलेगा. विगत एक सप्ताह में आसमानी बिजली से 17 लोगों की जानें गईं हैं। विभाग ने आगाह किया है जब बिजली गिरने की मैसेज आये तब घर से न निकले ।

श्री आईजी गौशाला में नवीन शेड निर्माण के उद्घाटन में उपस्थित श्री आईजी गौशाला अध्यक्ष मंगलाराम पंवार सचिव हुकमाराम सानपुरा ,सह सचिव ढगलाराम सेपटा , कोषाध्यक्ष नारायणलाल परिहार, सलाहकार डायाराम लचेटा, भंवरलाल मुलेवा, पारसमल शर्मा,सीरवी समाज पारसीगुटा वडेर अध्यक्ष मोहनलाल हाम्बड़, सीरवी समाज कोरेमुला वडेर अध्यक्ष कालुराम काग, राजस्थान पधारे बुलादा के उप सरपंच भंगाराम प्रजापत, लुंबाराम गुर्जर चैनाई पधारे केसाराम, कोषाध्यक्ष महाबलिपुरम बडेर कोषाध्यक्ष बुधाराम , विजयराज, सचिव शेषाराम, महिला मंडल चैनाई कमला बाई ,रामुबाई, भंवरी बाई, गीत, मैना देवी, प्रेमा देवी,श्री आईजी गौशाला समस्त कार्यकारणी व गौभक्त ।

"गिरती छतें, गिरती ज़मीर: झालावाड़ हादसा और हमारी व्यवस्था की नींव में छुपी मौत"

✍ प्रियंका सौरभ

राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई। और उसके नीचे दबकर कुछ मासूम टाबर – वो बच्चे जिनकी आँखों में सपने थे, जिनकी किताबों में भविष्य था – हमेशा के लिए ख़ामोश हो गए। किसी ने कहा, श्ये एक हादसा थाश। मगर जिन लोगों की ज़िंदगियाँ मिट्टी में मिल गईं, उनके लिए यह हादसा नहीं था। यह हत्या थी। और कातिल हम सब हैं – चाहे सरकारी सिस्टम हो, प्रशासन, ठेकेदार, या समाज।

हमारा समाज कब इतना संवेदनहीन हो गया कि एक स्कूल की छत गिर जाने की ख़बर पर भी सिर्फ सोशल मीडिया पर 'श्रद्धांजलि' और 'दुःखद' लिखकर आगे बढ़ जाता है? क्या हमने इतनी जल्दी सीख लिया है, बच्चों की मौत को 'न्यू नॉर्मल' की तरह स्वीकार करना?

हर ईंट एक गवाही देती है कि इस स्कूल की छत कमजोर नहीं थी—उसकी नींव में ही भ्रष्टाचार घुला था। बिल्डिंग के नक्शे से लेकर निर्माण सामग्री तक, हर कदम पर कोई न कोई ईमानदारी से भागा। और जब ईमानदारी भागती है, तब ज़मीर गिरती है। और जब ज़मीर गिरती है, तब छतें गिरती हैं, मासूम दबते हैं।

आप ठेकेदार हैं? आप मिस्त्री हैं? आप इंजीनियर हैं? तो आप जिम्मेदार हैं। अगर आपने रिश्वत खाई, अगर आपने सस्ती सामग्री का इस्तेमाल किया, अगर आपने आँखें मूंदी, तो आप हत्यारे हैं। और यह शब्द मैं हल्के में नहीं कह रहा।

आज जो छत गिरी है, वह सिर्फ सीमेंट और सरिए की बनी नहीं थी—वह हमारे भरोसे, हमारी ज़िम्मेदारी और हमारे संविधान की आत्मा की छत थी। जब वो गिरी, तो यह संकेत था कि इस देश का लोककल्याण का वादा अब केवल कागज़ पर बचा है।

सवाल यह भी है कि इन हादसों के बाद जांच कौन करता है? वही विभाग जिनके अधिकारियों ने निर्माण के समय आँखें मूँदी थीं? वही नेता जिनके इशारे पर टेंडर बाँटे गए थे? क्या हमने कभी देखा है कि किसी मंत्री को ऐसे हादसे के लिए इस्तीफा देना पड़ा हो? शायद नहीं। क्योंकि हमारे देश में पद की गरिमा बची है, जिम्मेदारी नहीं।

झालावाड़ की घटना से पहले भी कई बार यह ज़मीर हिली है। मध्य प्रदेश में स्कूल की दीवार गिरने से सात बच्चे मरे थे। उत्तर प्रदेश में पुल के उद्घाटन के तीन दिन बाद ही वह टूट गया था। बिहार में अस्पताल की छत का हिस्सा गिरा और एक मरीज की मौत हो गई। यह हादसे नहीं, पैटर्न हैं। और इस पैटर्न का नाम है—"ठेकेदारी तंत्र"।

यह तंत्र राजनीति, नौकरशाही और व्यापार का त्रिकोण है, जिसमें नीचे हमेशा जनता दबती है। और जब जनता स्कूल में पढ़ते बच्चों के रूप में दबती है, तब यह त्रिकोण त्रासदी बन जाता है।

हमारा सिस्टम सिर्फ ज़िम्मेदार नहीं है, वो संवेदनहीन भी हो चला है। हर मरे हुए बच्चे पर नेता दुख जताते हैं, मुआवज़े की घोषणा करते हैं, और फिर किसी अगली चुनावी रैली में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन एक माँ के लिए मुआवज़ा क्या होता है? वो बच्चा जो दोपहर की छुट्टी के बाद लौटने वाला था, वो अब सफेद चादर में लिपट कर लौटता है। क्या कोई रकम उस आँचल की गर्मी लौटा सकती है जिसमें अब सिर्फ सूनापन बचा है?

हमें यह भी सोचना होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या हमारे स्कूल भवन इतने पुराने हैं? नहीं। कई जगह हाल ही में बने स्कूल भी गिर रहे हैं। असली वजह है—

मानक प्रक्रिया का पालन न करना। स्कूल भवन बनाने में सस्ती सामग्री का प्रयोग, स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, टेंडर प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद, और निर्माण के समय तकनीकी निरीक्षण का अभाव।

सरकारें योजनाएं बनाती हैं—"सर्वशिक्षा अभियानश, श्समग्र शिक्षा अभियानश, श्स्कूल चलें हमश—लेकिन क्या कोई अभियान श्स्कूल बचे रहेंश भी है? क्या कोई योजना बच्चों की जान बचाने के लिए है? या फिर वो सिर्फ आँकड़ों के लिए हैं?

यहां एक और पहलू देखिए—ग्रामीण इलाकों में कई स्कूल तो पंचायत की ज़मीन पर बने हैं, जिनका न तो नियमित निरीक्षण होता है, न ही मरम्मत। कई जगह प्रधान ही ठेकेदार होता है, और उसके निर्माण में 'गुणवत्ता' शब्द मज़ाक बनकर रह जाता है। यहाँ तक कि कहीं-कहीं सरकारी स्कूलों की दीवारें पोस्टरों और नारों से पटी होती हैं—श्पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडियाश—लेकिन दीवार के अंदर बालू और भ्रष्टाचार से बनी ईंटें सांस ले रही होती हैं।

समस्या केवल भवन की नहीं है, पूरी मानसिकता की है। जब तक हम हर सरकारी काम को 'चलता है' की मानसिकता से देखते रहेंगे, तब तक छतें गिरती रहेंगी। और हर छत के साथ कुछ सपने, कुछ हँसते चेहरें और कुछ माँ-बाप की पूरी दुनिया ढहती रहेगी।

हमें अब बदलाव की शुरुआत करनी होगी—जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हर सरकारी निर्माण का 'Live Audit' होना चाहिए। निर्माण सामग्री की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा होनी चाहिए। RTI के माध्यम से स्कूल भवनों की गुणवत्ता की रिपोर्ट जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। निर्माण कार्यों में स्थानीय समाज को निगरानी का अधिकार देना चाहिए।

सिर्फ यही नहीं, अब न्यायिक हस्तक्षेप भी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मामलों में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। निर्माण में लापरवाही को 'क्रिमिनल नेग्लिजेंस' मानकर दोषियों पर गैर-जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज होने चाहिए।

अब वक्त आ गया है कि समाज भी अपनी भूमिका समझे। हर मोहल्ले, हर गाँव में लोगों को पूछना चाहिए—हमारे बच्चों का स्कूल सुरक्षित है या नहीं? अगर नहीं, तो आवाज़ उठानी चाहिए। चुप रहना भी अपराध है।

पत्रकारों को भी घटनास्थल पर जाकर खबरें बनानी चाहिए, सिर्फ "X बच्चे मरे" जैसी हेडलाइनों से आगे बढ़कर यह पूछना चाहिए—"क्यों मरे?" "किसकी लापरवाही?" और "अब क्या कार्रवाई?" पत्रकारिता अगर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रह गई, तो वह भी इस व्यवस्था की ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकती।

झालावाड़ के उन मासूम बच्चों की आत्मा भले ही अब इस दुनिया में न हो, लेकिन उनकी यादें हमें यह याद दिलाती रहेंगी कि हमारी खामोशी किस हद तक खतरनाक हो सकती है। हर बच्चा जो उस स्कूल में पढ़ने गया था, उसने देश के भविष्य में निवेश किया था। मगर बदले में हमने उसे मलबे में दफना दिया।

जब अगली बार आप किसी इमारत को बनते देखें, तो सिर्फ यह मत देखिए कि वह कितनी ऊँची होगी, यह भी सोचिए कि उसकी नींव में ईमान है या नहीं। क्योंकि अगर नींव में लालच, लापरवाही और भ्रष्टाचार है, तो वह इमारत नहीं, कब्र है।

आज जो मलबा झालावाड़ में बिखरा है, वह सिर्फ एक इमारत का नहीं है, वह हमारी सोच, हमारी जिम्मेदारी और हमारी संवेदना का भी मलबा है।

उन बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं चाहिए—उन्हें इंसाफ़ चाहिए। और इंसाफ़ तब होगा जब हमारी व्यवस्था की छतें फिर से मजबूत होंगी। जब हर ईंट में ईमानदारी होगी। जब ठेकेदार अपनी ज़मीर से निर्माण करेगा। जब अधिकारी निरीक्षण में ग़फलत नहीं करेगा। जब समाज ख़ामोश नहीं रहेगा।

आख़िर में एक सवाल—

हर टूटती छत, हर गिरती दीवार हमसे पूछ रही है—क्या अब भी तुम्हारी ज़मीर ज़िंदा है?

हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा

डॉ. सत्यवान 'सौरभ'

हिंदी है दिल की धड़कन, हिंदी है प्राण हमारा,
हिंदी से ही जुड़ा हुआ, भारत देश प्यारा।
नदियों सी बहती हिंदी, सागर सी गहराई,
संस्कृति की पालकी बनकर, सबको रही लुभाई।
वेदों की वह वाणी है, संतों की यह बोली,
मीरा, तुलसी, कबीर की, इसमें बसी ठिठोली।
गांधी के स्वप्नों की भाषा, अटल का अभिमान,
हिंदी से ही खिल उठता है, मेरा हिंदुस्तान।
दफ्तर की दीवारों पर अब, हिंदी मुस्काए,
काग़ज़-कलम से लेकर कंप्यूटर तक जाए।
राजभाषा का गौरव पाकर, करे नया आगाज़,
हर पख़वाड़े में हिंदी बोले, सारा हिन्द समाज।
कभी मत समझो कमजोर इसे, यह जन-जन की आवाज़,
हर दिल में है बसी हुई, इसकी गूँजे राज़।
अंग्रेज़ी से बैर नहीं, बस अपनी पहचान रहे,
दुनिया जाने भारत को, हिंदी की पहचान कहे।
बच्चों को पढ़ाओ इसे, खुद भी इसका मान करो,
जिस मिट्टी में जन्मे हो तुम, उसका सम्मान करो।
कलम उठे जब भाव लिखो, हिंदी में मुस्कान हो,
शब्दों में हो आत्मा ऐसी, जो भारत की जान हो।

संदेश:

हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, यह भारत की आत्मा है। आइए, हिंदी पख़वाड़े में इसे और ऊँचाई दें।

शिक्षक या चप्पल निरीक्षक? CET ड्यूटी का अपमानजनक आदेश

✍ डॉ सत्यवान सौरभ

हरियाणा सरकार द्वारा CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) परीक्षा के दौरान शिक्षकों को बस स्टैंडों पर ड्यूटी देने का निर्णय महज एक प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर प्रहार है। हरियाणा भर में जिस तरह अध्यापकों ने हाथों में बैनर लेकर श्हमें परीक्षा केंद्र दो, न कि बस अड्डाश, जैसे नारे लगाए — वह केवल व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश नहीं था, वह शैक्षिक गरिमा की चीख थी।

क्या यह वही समाज है जो गुरुओं को भगवान से ऊँचा मानता है? या फिर वही तंत्र है जो शिक्षक को परीक्षा के दिन एक 'ड्राइवर मैनेजर' या 'चप्पल गिनने वाला' बना देता है?

शिक्षक नहीं, सेवक बना दिए गए हैं!

हरियाणा में हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो वर्षों से बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। मगर जब राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग जैसे संस्थान इन्हें बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर देते हैं — तो सवाल उठता है कि क्या शिक्षक अब शिक्षा से हटाकर व्यवस्था की गुलामी में धकेले जा रहे हैं?

पानीपत, करनाल, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित हरियाणा के जिलों में CET परीक्षा के लिए शिक्षकों को पेपर ड्यूटी की बजाय ट्रैफिक, पार्किंग और अभ्यर्थियों के इंतजार स्थलों पर भेजा गया। यानी वे पूछते रहे – "आपका सेंटर कहां है? चप्पल बाहर उतारिए।" क्या यही उनकी भूमिका है?

सरकार की नीयत पर सवाल

सरकार अक्सर शिक्षकों से अपेक्षा करती है कि वे ईमानदारी से कार्य करें – चाहे चुनाव हो, जनगणना हो, बाढ़ राहत हो या परीक्षा। और शिक्षक हर बार बिना विरोध किए डटकर खड़े भी रहते हैं।

मगर जब परीक्षा से जुड़े दिन, जहाँ उनकी शैक्षणिक क्षमता सबसे ज़रूरी होती है, उन्हें शिक्षा व्यवस्था से बाहर खड़ा कर दिया जाता है, तो यह न केवल तर्कहीन है बल्कि अपमानजनक भी।

क्या शिक्षा विभाग को यह समझ नहीं आता कि एक शिक्षक परीक्षा केंद्र में अनुशासन बनाए रखने और कदाचार रोकने में सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी होता है?

प्रशासनिक सहूलियत या मानसिक लापरवाही?

प्रशासन का कहना है कि बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के कारण ट्रैफिक नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए स्टाफ चाहिए। यह तर्क अपनी जगह सही हो सकता है, पर क्या इसके लिए शिक्षकों को ही चुना जाना आवश्यक था? क्या पुलिस, NCC कैडेट्स, NSS वालंटियर्स या अस्थायी ड्यूटी कर्मी नहीं हो सकते?

शिक्षक कोई चाकरी करने वाला नहीं। वह समाज के बौद्धिक नेतृत्व का प्रतिनिधि होता है।

जब वही हाथ बस अड्डे की सीढ़ियों पर खड़े होकर नाम पुकारें,

और वही आँखें जूते-चप्पलों की निगरानी करें,

तो यह पूरी व्यवस्था की सोच का दीवालियापन है।

हरियाणा में विरोध क्यों भड़का?

CET ड्यूटी के खिलाफ हरियाणा के अनेक जिलों में सरकारी अध्यापकों ने खुलेआम प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा ड्यूटी एक अकादमिक जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्किंग स्थल, वेटिंग जोन, और पानी वितरण काउंटरों पर खड़ा किया जा रहा है — बिना ट्रेनिंग, बिना छाया, बिना मूलभूत सुविधाओं के।

एक महिला शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह कह रही थी —

"हमें शिक्षा की जिम्मेदारी दीजिए, व्यवस्था की नहीं। हम शिक्षक हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं।"

ऐसे हालात में शिक्षकों का आक्रोश अकारण नहीं।

क्या परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त स्टाफ नहीं था?

एक बड़ी चिंता यह भी है कि जब शिक्षकों को बस स्टैंड भेजा गया, तो परीक्षा केंद्रों पर आउटसोर्स कर्मचारियों और निजी स्कूलों के अस्थायी कर्मचारियों से काम चलाया गया।

यह प्रश्न उठता है कि आखिर शिक्षा की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसके पास है?

क्या सरकारी शिक्षक केवल 'फिलर' हैं जिन्हें जहाँ चाहा, खड़ा कर दिया?

शिक्षक की गरिमा का क्षरण क्यों?

भारत का इतिहास रहा है कि जहाँ शिक्षक बोलते थे, वहाँ राजा झुकते थे। चाणक्य से लेकर अब्दुल

कलाम तक, यह परंपरा रही है कि शिक्षक नीतियों का निर्माता होता है, पहरेदार नहीं।

मगर अफ़सोस कि अब वही शिक्षक ड्यूटी चार्ट में एक नंबर बनकर रह गया है — "08:00 से 05:00, लोकेशनः बस स्टैंड, कार्यः उम्मीदवारों को दिशा-निर्देश देना।"

क्या आज शिक्षक सम्मान मांगता है, या सिर्फ अपना कर्तव्य याद दिला रहा है?

समझिए शिक्षक का मनोविज्ञान

शिक्षक का कार्य न सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, बल्कि परीक्षा जैसे आयोजनों में नैतिकता और अनुशासन को बचाए रखना भी है। मगर जब वही शिक्षक अनुशासनहीन भीड़ के बीच, सार्वजनिक स्थल पर, किसी पहचान के बिना खड़ा कर दिया जाता है, तो उसका आत्मविश्वास टूटता है।

इसका असर न सिर्फ उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि आने वाले समय में उसकी जिम्मेदारी निभाने की इच्छा पर भी।

शिक्षा विभाग की चुप्पी और राजनीतिक सन्नाटा

सवाल यह है कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री, HSSC, और जिला उपायुक्त जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग चुप क्यों हैं?

क्या यह शिक्षक समुदाय की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं, या उन्हें इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती?

राजनीतिक दलों ने भी अभी तक इस मुद्दे पर जिम्मेदारी से न प्रतिक्रिया दी, न समाधान सुझाया।

शिक्षकों को केवल चुनावी सभा में श्बुद्धिजीवी वर्गश कह देने से काम नहीं चलेगा।

क्या यह आंदोलन और तेज होगा?

शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में भी इसी तरह की ड्यूटी लगाई गई, तो वे CET और अन्य परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे।

यानी बात सिर्फ CET 2025 की नहीं, बल्कि एक व्यापक असंतोष की शुरुआत हो चुकी है।

समाधान क्या हो सकता है?

1. ड्यूटी निर्धारण में पारदर्शिता — शिक्षकों को केवल अकादमिक कार्यों में लगाया जाए।

2. बदलाव लाएं वैकल्पिक संसाधनों से — ट्रैफिक व गाइडेंस कार्यों के लिए प्रशिक्षित गैर-शैक्षणिक कर्मचारी तैनात किए जाएं।

3. शिक्षकों के साथ संवाद — फैसलों से पहले प्रतिनिधियों की राय ली जाए।

4. आत्मसम्मान की सुरक्षा — शिक्षकों को प्रशासनिक व्यवस्थाओं का 'लोगतांत्रिक श्रमिक' न समझा जाए।

अंतिम शब्दः शिक्षा बचाइए, शिक्षकों को मत खोइए

एक शिक्षक को परीक्षा केंद्र से बाहर भेज देना,

उसके ज्ञान से अधिक उसके शरीर का उपयोग करना,

और फिर उसके मौन से यह उम्मीद करना कि वह हर बार बिना सवाल किए व्यवस्था का हिस्सा बना रहेगा —

यह सोच हमें एक दिन उन गुरुओं से वंचित कर देगी, जिनसे हम भविष्य की आशा करते हैं।

समय आ गया है कि सरकार, समाज और सिस्टम,

शिक्षक को फिर से "कर्मचारी" नहीं, "गुरु" माने।

वरना अगली पीढ़ियाँ जब पूछेंगी —

श्पढ़ाने वाला चप्पल गिनता क्यों था?श

तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं होगा।

8 विपक्षी दलों के एक राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा के राज्यपाल से मुलाकात की

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भुवनेश्वर :-ओडिशा के राज्यपाल को आज दोपहर महिलाओं के लिए न्याय की मांग को लेकर राज्य के 8 विपक्षी दलों ने एक ज्ञापन सौंपा। 8 विपक्षी दलों के एक राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा के राज्यपाल से मुलाकात कर महिलाओं के लिए न्याय और देश में व्यवस्थागत विफलताओं की मांग की। इस ज्ञापन में राज्य सरकार को महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

मांग की गई है कि एक महिला न्यायाधीश के नेतृत्व में एक न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया जाए, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों और व्यवस्थागत विफलताओं के कारणों की जाँच करेगा और 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

संयुक्त विपक्षी दलों ने पुलिस व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने की माँग की है।

मांग की गई है कि संस्थागत सुधार लाने के लिए ओडिशा राज्य महिला आयोग में तत्काल एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। ओडिशा में महिलाओं से संबंधित 11,000 से अधिक लंबित शिकायतों का तत्काल

समाधान किया जाए। महिला पुलिस थाने और टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की जाएँ। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामलों का निपटारा 6 महीने की समय-सीमा के भीतर करने की माँग की गई है। ओडिशा में महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि दर को राष्ट्रीय दर 8.3% से बढ़ाकर 26.6% करने की माँग की गई है। नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाए और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में नियमित जागरूकता और निगरानी की व्यवस्था की जाए। सार्वजनिक स्थानों पर बिजली, सीसीटीवी, पुलिस गश्त और अन्य संबंधित सुरक्षा उपाय बढ़ाए जाएँ। जस्टिस बर्मा समिति की सिफारिशों के अनुसार सुरक्षा कड़ी की जाए। यौन अपराध मामलों की संवेदनशील जाँच के लिए पुलिस को प्रशिक्षित किया जाए। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था लागू करने की माँग की गई है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएँ। कौशल विकास और रोज़गार प्रदान करके महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए।

पुलिस थानों में बलात्कार और यौन अपराध रिकॉर्ड के लिए विशेष प्रकोष्ठ और ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की जाए। संयुक्त विपक्षी दलों ने महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सभी स्तरों के लोगों, महिला संगठनों, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पीड़ित परिवारों के साथ नियमित परामर्श की माँग की है।

उन्होंने विभिन्न आवासीय विद्यालयों में नाबालिगों की तस्करी और यौन शोषण को रोकने के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था के साथ-साथ आरोपियों के विरुद्ध कठोर दंड की मांग की है।

प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास, कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जयदेव जेना, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी बहिनीपति, वरिष्ठ विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति, भाकपा के राज्य संयुक्त सचिव डॉ. प्रशांत कुमार मिश्रा, राज्य सचिव संघवी जयंत दास, माकपा के राज्य सचिव सुरेश चंद्र पाणिग्रही, भाकपा (माले)-लिबरेशन के राज्य सचिव युधिष्ठिर महापात्र, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के राज्य महासचिव ज्योति रंजन महापात्र, राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम स्वैन, सपा के प्रदेश महासचिव , राजद के प्रदेश महासचिव हेमंत कुमार शामिल थे।

तारा का तीर: कहा हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए संख्याबल, बीजेडी ने नहीं किया

मनोरंजन सासमल

भूबनेश्वर: जयपुर से विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता तारा बहिनीपति ने अविश्वास प्रस्ताव पर निशाना साधा है। तारा ने कहा, श्हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पर्याप्त संख्या है। हमारे पास 14 विधायक हैं और हमारे पास एक सीपीआई विधायक है। अगर बीजेडी समर्थन नहीं करती है, तो यह माना जाएगा कि हम बीजेपी के साथ हैं। अविश्वास प्रस्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतदान के बाद पता चलेगा।

इस बीच, बालासोर एफएम कॉलेज की छात्रा की आत्महत्या की घटना ने राज्य की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने एक प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और घोषणा की कि अगर बीजू जनता दल (बीजद) सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, अगर बीजद महिलाओं के न्याय के लिए ईमानदारी से लड़ रही है, तो उसे विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। हम इसका समर्थन करेंगे।

अन्यथा, हम खुद अविश्वास प्रस्ताव

लाएँगे और बीजद उसका समर्थन करेगा। बालासोर की घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए दास ने कहा, हम सभी इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि राज्य सरकार को इस पर कोई शर्म नहीं है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार अब तक मूकदर्शक बनी हुई है और महिला आयोग का गठन करने में विफल रही है। उन्होंने इस घटना में न्याय के लिए उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से न्यायिक जाँच की माँग की है।

दूसरी ओर, बीजद ने भी इस घटना को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। बीजद ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि एफएम कॉलेज की छात्रा की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पार्टी ने इस घटना में न्याय की माँग को लेकर लोक सेवा भवन और तीन क्षेत्रीय विकास परिषदों के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। बीजद नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है और कॉलेज परिसरों में छात्र सुरक्षित नहीं हैं।

एक पूर्व पोस्ट में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस और बीजद को अविश्वास प्रस्ताव पर संयुक्त रूप से सहमत होना चाहिए। पोस्ट में कहा गया है, 'जो पार्टी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती है, उसे नैतिक आधार पर सरकार विरोधी आंदोलन से बचना चाहिए।'

इस घटना को लेकर राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस और बीजद दोनों ही महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि, अविश्वास प्रस्ताव लाने के बीजद के औपचारिक निर्णय की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच, इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार ने इस घटना की न्यायिक जाँच कराने और महिला आयोग गठित करने के लिए कोई कदम उठाया है।

इस घटना ने ओडिशा के राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। आने वाले दिनों में विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस और बीजद के अगले कदमों पर सबकी नज़र है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023